

हवाई चप्पल का इतिहास और इसके पॉपुलर होने की कहानी

[संजय कुंदन]

आज से करीब बीस साल पहले मेरा एक मित्र एनएसडी में दाखिला लेने पटना से दिल्ली आया, तो यहाँ कुछ दिन बाद किसी ने उससे पूछा कि दिल्ली और पटना में क्या अंतर है? उसने जवाब दिया कि बस एक अंतर है। पटना में मैं हवाई चप्पल पहनकर घूमता था और दिल्ली में जूता पहनकर घूमता हूँ। छोटे शहरों में हवाई चप्पल पहनकर घूमना आम बात रही है, खासकर पंद्रह-बीस साल पहले। हमलोग घर में भी हवाई चप्पल पहनते थे और वही पहनकर अक्सर कॉलेज और मार्केट भी चले जाते थे। विशेषकर फैशन से बेपरवाह, कला-साहित्य और थियेटर से जुड़े लोगों को इसमें संकोच नहीं होता था। हवाई चप्पल अक्सर साझा हुआ करती थी। अब परिवार में तीन भाई हैं। जिसको जो चप्पल मिली, वह पहनकर निकल लेता था। साइंज थोड़ा कम या ज्यादा भी हो, तो फर्क नहीं पड़ता था। कुछ घरों में चार लोगों पर दो चप्पल होती

थीं। अक्सर ये बाथरूम के पास रखी होती थीं, जिसे जाना होता था, वो पहन लेता। उस समय की चप्पलें बड़ी साधारण हुआ करती थीं। बस एक सफेद सोल होता था, जिस पर दो रंगीन फीते लगे होते थे। हालांकि उन्हीं दिनों एक मोटी गहेदार सोल वाली रंग-बिरंगी चप्पलें भी आईं जिन्हें पता नहीं क्यों नेपाली चप्पल कहा जाता था। लेकिन उन्हें पहनने पर पैर फिसलते थे, सो वे जलदी ही चलन से बाहर हो गईं। मैं हाल में एक शोरूम में चप्पल खरीदने गया तो मुझे डिजाइनर रंगीन चप्पलें पकड़ा दी गईं, जिसका सोल काफी मजबूत था और फीते भी काफी सुंदर थे। पर यह वह चप्पल नहीं थी, जिन्हें पहनकर मैं कॉलेज के दिनों में घूमता था। वैसे यह सवाल है कि इसे हवाई चप्पल क्यों कहते हैं? एक राय यह है कि इसे यह नाम अमेरिकी द्वीप 'हवाई' से मिला है। अमेरिका के हवाई द्वीप में 'टी' नाम का एक पेड़ होता है जिससे तैयार रबरनुमा



RNI CHHHIN/2011/140074



छत्तीसगढ़ राज्य

वर्ष : 08, अंक : 10, सितंबर 2019

संपादक
चन्द्रभूषण वर्माप्रबंध संपादक
रीतेश शर्मासलाहकार संपादक
अरुण चौधे, पूरन सिंह
संकर्षण शरण जी महाराज

संवाददाता
रशिम शर्मा (दिल्ली)
मिलिन्द (नागपुर)
अजीत पटेल (बिहार)
आशीष दुबे (भोपाल)
सुधीर अग्निहोत्री (उत्तरप्रदेश)
चन्द्ररूपा सिंह (ओडिशा)
मनीष जोशी (रायपुर)
मुकेश टिकिराहा (रायपुर)
कुमार नायर (धमतरी)
सलीम रजा उस्मानी (दत्तेवाड़ा)
भूपेन्द्र वर्मा (भानपुरी बस्तर)
अनिल सिंह (अंबिकापुर)
प्रदीप मौर्य (राजनांदगाँव)

विधि सलाहकार
परिमल डॉनगावकरले-आठट एवं ग्राफिक्स
सर्येन्द्र कुमार सिंहसंपादकीय कार्यालय
गायत्री नगर, आशीर्वाद हॉस्पिटल के पास
डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)

स्वामी प्रकाशक मुद्रक चंद्रभूषण वर्मा
द्वारा गायत्री नगर, आशीर्वाद हॉस्पिटल
के पास, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) से
प्रकाशित तथा प्रिंटेक स्कैनर, मिश्शा
बाड़ी, तात्यापारा चौक, रायपुर (छ.ग.)
से मुद्रित भोबाइल : 98262-37000
E-mail : chandrabhushanverma555@gmail.com

प्रकाशित रचनाओं के विचारों से संपादक का
सहमत होना जरूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य
से संवर्धित सभी विवादास्पद मामले
रायपुर न्यायालय के अधीन होंगे

अन्दर के पृष्ठों पर...



03

कश्मीर में नई सुबह का आगाज खत्म हुआ एक इतिहास
कश्मीर पर बुद्धिजीवियों की तकलीफ!
धारा 370-मोदी सरकार का अत्यंत प्रशंसनीय कदम
सौविधान को मिला नया विस्तार

करवट ले रहा है विकास

18

भारतीय राजनीति का अमिट आलेख हैं
सुषमा स्वराज

24



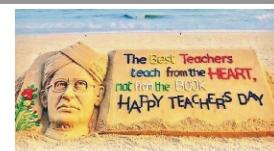
28

मुश्किलों का अंबार है, रुपया परवरदिगार है



29

सड़क पर सारे ऐक्सडेंट एक ही वजह से नहीं होते



30

रस्म भर न रह जाए शिक्षक दिवस



32

क्या संभव है प्लास्टिक से मुक्ति और
कितनी कारगर होगी हर्बल प्लास्टिक
प्रतिदिन 9000 हथियों के बराबर
पैदा होता है प्लास्टिक कचरा
इसलिए पीएम ने की अपील

हमारे मासिक पत्रिका में छपे विज्ञापनों के लिए मासिक पत्रिका
छत्तीसगढ़ राज्य उत्तरदायी नहीं है, विज्ञापनों में प्रकाशित विचार
विज्ञापनदाता की निजी राय है इससे मासिक पत्रिका का कोई संबंध नहीं है



चन्द्रभूषण वर्मा

नई पीढ़ी बदल रही है पितृपक्ष की पुरानी परंपरा

कहा जाता है कि पूर्वजों से जो हमें विरासत में मिलता है, उसी पर आगे चलकर नई इबारत लिखी जाती है। श्राद्ध भी एक ऐसा ही अवसर है, जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनकी विरासत संभालते हैं। उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसके लिए तर्पण जैसे कर्मकांड भी हैं। मान्यता है कि इससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। लेकिन वर्तमान में पूर्वजों की तृप्ति के नए सोपान बन रहे हैं। समाज में वर्जनाएं टूट रही हैं और एक नया समाज रचा जा रहा है। इस समाज में धर्म तो है। मान्यताएं और कर्मकांड भी हैं। लेकिन अब यह किसी के लिए वर्जनीय क्षेत्र नहीं रहा।

एक समय वह था, जब समाज पर धार्मिक मान्यताएं हावी थीं। लोग टस से मस नहीं होते थे। पितृ पक्ष को ही लें। पहले इसमें स्त्रियों की भूमिका सीमित थी। मान्यता यह है कि जब घर में कोई पुरुष सदस्य न हो, तभी महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। लेकिन अब कहीं बेटियां अपने पिता का श्राद्ध करती हैं, तो कहीं पत्नी अपने पिता का श्राद्ध कर रही है। पिता का श्राद्ध करने वाली एक महिला ने बताया- ‘शुरू में मुझे इससे रोका गया। कहा गया कि स्त्री को यह अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी जिद के आगे ये बाधाएं टूट गईं। आज मैं उसी तरह श्राद्ध करती हूं, जैसे बाकी लोग करते हैं। मैं केवल पर्दियों को भोजन कराने की बजाय कुछ ठोस करना चाहती थी, इसलिए बच्चों को गोद ले लिया। पिता का स्मरण करते हुए हर साल कम से कम दो बच्चों को गोद लेती हूं’। इसी तरह एक बेटी है, जो अपने पिता का श्राद्ध करती है। शादी हो गई, लेकिन संसुराल में भी कर रही है।

पहले श्राद्ध पक्ष को निषिद्ध-काल माना जाता था। नया कुछ खरीदा नहीं जाता था। बाल कटाना, शेव बनाना तक बंद हो जाता था। घर में छाँक तक नहीं लगता था। जिस दिन पूर्वज का श्राद्ध होता था, उस दिन तो सारे कार्य ही मना थे। पहले इस दौरान व्यापारी माल नहीं मंगवाते थे। उनके लिए ये 16 दिन शांत बैठने वाले होते थे। लेकिन अब परंपराएं बदल रही हैं। बाजार शांत नहीं रहा अब। खरीदारी होने लगी है। श्राद्ध पक्ष में एक नई अवधारणा ने भी जन्म लिया है कि पितृ आपको, हमको और अपने घर को खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए, यहां उन पुरानी वर्जनाओं का कोई मतलब नहीं रहा, जो सदियों से चली आ रही हैं।

हमेशा से पितृ पक्ष का दूसरा पहलू सामाजिक सरोकार है। तब पितरों की याद को बरकरार रखने के लिए समाज का धनाद्य वर्ग आगे आता था। लोग अस्पताल, कॉलेज, धर्मशालाएं बनवाते थे। व्याऊ बनवाते थे। किसी भी शहर में चले जाइए, पूर्वजों के नाम पर ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। समय के साथ इसमें कुछ तब्दीली आई है। धर्मशालाएं बनाने का दौर तो अब खत्म हो गया, लेकिन अस्पताल, नर्सिंग होम और कॉलेज के लिए दान का काम खूब होता है। नई पीढ़ी ने पितृ पक्ष का पूरा कलेकर ही बदल दिया है। उसने इसके कर्मकांड को शिक्षा से अधिक जोड़ा है। नर से नारायण की सेवा करते हुए अब पितृ पक्ष पर पर्दियों को भोजन के साथ उनके बच्चों को कॉपी-किटाबें दी जाने लगी हैं। कुछ लोग तो इस दौरान अनाथालय, वृद्धाश्रमों की ओर रुख करने लगे हैं।

कुछ जगहों पर पितरों की याद में पौधे रोपे जाते हैं। कोई मेडिकल कैंप लगवाता है, तो कोई ब्लड डोनेशन कैंप। हाल-फिलहाल के वर्षों में पितृ अमावस्या के दिन ज्ञात-अज्ञात शहीदों के सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम आयोजित होने लगा है। श्राद्ध कर्म ‘अपनों’ की अवधारणा से बाहर निकला है। हम अपनों के लिए तो तर्पण करते ही हैं, उन लोगों के लिए भी यह करने लगे हैं, जिनका कोई नहीं है। समाज में बहुत से ऐसे लावारिस लोग होते हैं, जिनका संस्कार भी चंदे से होता है। कुछ संस्थाएं अब इनके लिए भी श्राद्ध करती हैं।

समाज पितृ पक्ष को नया कलेकर दे रहा है। अब श्राद्ध पक्ष केवल तर्पण तक सीमित नहीं रहा। समाज के लिए अर्पण भी है। श्राद्ध पक्ष में उपेक्षित, तिरस्कृत, अभावग्रस्त समुदायों के प्रति लोग श्रद्धावनत हो रहे हैं। इस पक्ष पर किसी का एकाधिकार नहीं रहा। पूर्वज भले ही सशरीर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, स्मृतियां सदैव हमारे साथ रहती हैं।



हे ! कागदेव : पितृपक्षे नमस्तुभ्यम्

[प्रभुनाथ शुक्ल]

सुखाय का जाप करती हैं और मां-बाप को

बोझ समझती हैं। परलोकवासी होने के बाद झूठे सम्मान में तेरहवीं पर देशी थी का भोज करते हैं। हे कागदेव ! ऐसे प्राणियों

को आप कब सहुद्धि दोगे।

हे ! काग स्वरूप में श्रद्धेय पितर जी। मुझे माफ करना। मेरे व्यंग तीर से आप आहत मत होना। लोग आपको बेहद कुरुप और चार्तुय प्राणी मानते हैं। हमरे साहित्य में आपकी ध्यान मुद्रा का वर्णन है। कहा भी गया है काक चेष्टा, बको ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी विद्यार्थियों में यह पांच लक्षण होने चाहिए। आपकी चंचलता भी अवर्णनीय है। जयंत आप ही हैं, जिसने तेत्रायुग में मां सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया था। जिसके बाद भगवान के कोप ने आपको एक आंख वाला पक्षी यानी एकाक्षी बना दिया। लेकिन कलयुग में इतना सम्मान दिया कि आप पितर की उपाधि से विभूषित हुए। पंचतंत्र में तो आप तेरुपत्र विश्रेष्ठ आपके तमाम अवगुणों में कई प्रकार के शुभ गुण भी विद्यमान हैं।

हे ! काग स्वरूप में अवरित पितरदेव। आप तो पक्षवारे भर हतुवा-पूड़ी और भाँति-भाँति के पकवान छक कर खाते हैं। खुद के तर्पण के लिए खोवे की व्यवस्था करते हैं। गंगा जल की तिलांजलि से प्यास बुझाते हैं। ब्राह्मणों पर धन की वर्षा करवाते हैं। वैदिकमंत्रों के बीच पिंडदान लेते हैं, लेकिन धरतीवासी अपने वंशजों का भी खयाल रखिए। वह बेचारे जर्जर शरीर में धरतीलोक में जिंदालाश की तरह पड़े हैं। पितर पक्षवारे में भी उन्हें कोई धास नहीं डालता। इनकी संख्या दो-चार नहीं लाखों में है। वृद्धा आश्रमों में जीवन गुजारते हैं। संताने देश-विदेश में स्वांतः

पितृपक्षे की कर्णफोड़ गीत में मेहमानों के आगमन का संदेश छुपा है। आपकी कुरुपता, धूर्तता और कर्कशा जैसे अवगुण भी कुछ गुणों की वजह से छुप जाते हैं। संस्कृत और हिंदी साहित्य आपका आजीवन ऋषी रहेगा। वैदिक साहित्य में आपकी धूर्तता और चालाकी के साथ बुद्धिमत्ता की कई कहानियां भी वर्णित हैं।

पितृपक्षे के अलावा अन्य दिनों में भी मुंदर आपका आगमन और कांव-कांव अप्रिय होने के बाद भी शुभ का सूचक है। आपकी इस कर्णफोड़ गीत में मेहमानों के आगमन का संदेश छुपा है। आपकी

कुरुपता, धूर्तता और कर्कशा जैसे अवगुण भी कुछ गुणों की वजह से छुप जाते हैं। कलिकाले, प्रथम चरणे।

पितृपक्षे, हे ! कागदेवो, नमस्तुभ्यम्, नमस्तुभ्यम् नमो नमः।

!! समाप्त !!

स्वतंत्र लेखक और पत्रकार

43

कहीं आपका बच्चा डिस्लेविसया का शिकार तो नहीं

अब स्कूली स्तर पर होगी इसकी पहचान

[शशांक शेखर भारद्वाज]

बीबीआइटी से आसान होगा बौद्धिक क्षमता का आकलन

आइआइटी कनाडा हैंदराबाद दिल्ली हरियाणा के विशेषज्ञों ने बीबीआइटी विकसित किया है स्कूली स्तर पर पकड़ में आएंगे न्यूरो संबंधी रोग। न्यूरो की एक समस्या ऐसी भी है जो बचपन में आसानी से नजर नहीं आती है। बच्चा देखने, बोलने और व्यवहार में बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उसे पढ़ने, लिखने और समझने में कठिनाई होती है। उसे पढ़ाई में कमज़ोर माना जाने लगता है जबकि वास्तविकता कुछ और रहती है। कुछ साल पहले आई अमिर खान अभिनीत फिल्म %तारे जर्मी पर% की कहानी ऐसे ही बच्चे पर आधारित थी। उसमें छात्र को डिस्लेविसया था, जिसकी वजह से अक्षर और रंगों को पहचानने में कठिनाई होती थी। ऐसी दिक्कतों को पहचानना भी मुश्किल भरा है। ऐसे ही न्यूरो संबंधी रोगों का स्कूली स्तर पर पहचान करना अब आसान हो गया है।

5 से 18 साल के छात्र शामिल

बीबीआइटी मुख्यता पांच से 18 साल के

आयु के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इस परीक्षण का स्तर कक्षा बढ़ने के साथ ही बढ़ता जाएगा। बौद्धिक क्षमता के आकलन में भाषा की जरूरत नहीं है। यह टेस्ट चिन्ह, निशान, चित्र, डिजाइन आदि पर आधारित रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक नौकरी के दौरान साक्षात्कार के लिए बीबीआइटी का प्रयोग किया जा सकता है। आकलन करना बेहद आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों ने देशभर के 1200 से अधिक छात्रों पर प्रयोग किया है, जिसके नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। बीबीआइटी को जाने लगता है जबकि वास्तविकता कुछ और रहती है। कुछ साल पहले आई अमिर खान अभिनीत फिल्म %तारे जर्मी पर% की कहानी ऐसे ही बच्चे पर आधारित थी। उसमें छात्र को

अक्षर और रंगों को पहचानने में कठिनाई होती थी। ऐसी दिक्कतों को पहचानना भी

मुश्किल भरा है। ऐसे ही न्यूरो संबंधी रोगों का स्कूली स्तर पर पहचान करना

अब आसान हो गया है।



करवट ले रहा है विकास

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने 8-9 माह के कार्यकाल में एक विशेष पहचान स्थापित की है। (इसमें ढाई से तीन माह तक लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचरण सहित प्रभावशील रही)। बात चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट - सुराजी गांव योजना नरुवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी के तहत की हो या फिर छत्तीसगढ़ के विकास की, शासन के मंशानुरूप जिला प्रशासन जुटा है कायाकल्प करने में।

पौनी पसारी : परम्परागत व्यवसायों को नया जीवन देने की पहल, बदलती हुई परिस्थितियों में जब गांवों ने नगरों का स्वरूप लिया तो इन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए हर घर में जाकर सुविधा देने में दिक्ष त होने लगी तब उनके लिए एक व्यवस्थित बाजार की कल्पना हुई। वर्तमान समय में युवाओं को रोजगार दिलाने में यह काम आज भी प्रासादिक है। छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील क्षेत्र सुकमा जिले के गांवों में गाय गोठान तेजी से आकार ले रहे हैं। 'गौ-संरक्षण और संवर्धन के लिए सार्थक साबित हो रहा गौठान', वहीं गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर पर दुर्गम पहाड़ी और बीहड़ जंगलों के बीच बसा ग्राम कुल्हाड़ीघाट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ करवट ले रहा है विकास...

‘बल्दीबाई’

पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी 17 जुलाई 1985 में पहुंचे थे कुल्हाड़ीघाट तब अपने हाथों से खिलाया था तेंदूफल



जिले के मैनपुर विकासखण्ड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर पर दुर्गम पहाड़ी और बीहड़ जंगलों के बीच बसा ग्राम कुल्हाड़ीघाट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्राम पंचायत कुल्हाड़ीघाट एवं उसके अश्रित गांव लगभग 35 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है। ताराझर, मटाल, भालुडिगी जैसे गांव दुर्गम एवं ऊंची पहाड़ों पर बसा हुआ है। यहां के लोग अभी भी पहाड़ी की तराई से होकर आना जाना करते हैं। यह क्षेत्र बनांचल, दुर्गम एवं संवेदनशील होने के साथ-साथ वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित है। इस ग्राम पंचायत की 1473 की आबादी में से लगभग 98 प्रतिशत आबादी विशेष पिछड़ी कमार जनजाति है। जब बल्दीबाई ने अपने हाथों से खिलाया कंदमूल ग्राम पंचायत कुल्हाड़ीघाट का मुख्यालय कुल्हाड़ीघाट में स्थित है। यह वही गांव हैं जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी सन् 1984 में अपनी पति श्रीमती सोनिया गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। तब से कुल्हाड़ीघाट को एक नई पहचान मिली है। गांव की महिला बल्दी बाई

ने अपने हाथों से राजीव गांधी को कंदमूल व तेंदूफल खिलाकर जैसे शबरी की भूमिका निभाई थी। आज लगभग 90 वर्ष की हो चुकी बल्दी बाई उन दिनों को याद करके चहक उठती है। उनकी चेहरे की झुर्रियों में चमक आ जाती है। वे बताती हैं कि उन्हें और उनके परिवार को शासन की पेंशन, राशन कार्ड, बन अधिकार पत्र एवं आवास योजना के तहत लाभ मिला है।

मानवीय विकास के बहुआयामी प्रयास

कमार विकास परियोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक आजीविका संवर्धन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण सहित सीधा लाभ दिया गया। इनमें 17 कमार परिवारों को भूमि, 28 को आवास एवं 471 व्यक्तिगत बन अधिकार पत्र दिये गये। बकरी पालन, मत्स्य पालन के लिए भी सहायता दी गई। यहां के कमार परिवारों को भूख से निजात दिलाने 179 अंत्योदय गुलाबी राशन कार्ड सहित 515 परिवारों का राशन कार्ड जारी किया गया है। यहां राशन दुकान के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन वितरित किया जा रहा है। जंगल एवं पहाड़ी के बीच रह रहे इन परिवारों के लिए अच्छा आवास भी चुनौती थी। शासन द्वारा इंदिरा आवास अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल 239 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 217 आवास पूर्ण हो गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 86 कमार परिवारों को आवास स्वीकृत

में भी पहुंच मार्ग से आ-जा सकते हैं। पंचायत में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ मानव संसाधन विकास के उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं।



पुरुषों को भी हो सकता है स्तन कैंसर कभी न करें इन 3 लक्षणों को नज़रअंदाज़

ये सच है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में काफी कम मात्रा में स्तन टिशू पाए जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों को स्तन कैंसर नहीं हो सकता। अक्सर स्तन कैंसर को सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है लेकिन सच्चाई ये है कि यह पुरुषों को भी अपनी चेपेट में ले सकता है। ये सच है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में काफी कम मात्रा में स्तन टिशू पाए जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों को स्तन कैंसर नहीं हो सकता। पुरुषों में स्तन कैंसर के मामले काफी कम पाए जाते हैं। हर साल एक प्रतिशत से भी कम पुरुषों को स्तन कैंसर होता है। हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिकी सिंगर बियॉन्से के पिता को स्तन कैंसर हो गया है।

आज हम आपको बता रहे हैं इस बीमारी के दौरान आपके शरीर में होने वाले बदलाव यानि इससे जुड़े लक्षणों के बारे में जिसके दिखते ही आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए।

ये हैं लक्षण

1. छाती पर गांठ

इन गांठों में अक्सर दर्द नहीं होता इसलिए छाती पर इसका होना पता नहीं चलता। इसके आपको तभी पता चलेगा जब आप छूकर परीक्षण करेंगे। आमतौर पर पुरुष छाती पर किसी भी तरह की गांठ को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा न करें क्योंकि यह ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैंसर जैसे-जैसे बढ़ेगा वह बग़ल, लिम्फ नोड्स और कॉलर बोन की

हड्डी के आस-पास तक फैल जाएगा।

2. निष्पल डिस्चर्ज

अगर आपको अपनी शर्ट पर अक्सर किसी तरह का दाग दिखता है तो सतर्क हो जाएं। ये भी हो सकता है कि यह चाय या कॉफी का हो, लेकिन अगर यह हर बार एक ही तरफ दिखता है तो यह निष्पल डिस्चर्ज का संकेत है। ऐसा द्यूमर की डिस्चर्ज की वजह से होता है जो निष्पल के ज़रिए बाहर आता है।

3. निष्पल का शेप बदलना

द्यूमर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही निगमेंट ब्रेस्ट के अंदर खिंच जाता है। ऐसे में निष्पल अंदर की ओर धंसने लगते हैं और उनका शेप बिगड़ जाता है।

बर्फ का एक टुकड़ा आपको खूबसूरत त्वचा दे सकता है यहीं नहीं इससे जुड़ी कई परेशानियां को भी दूर कर सकता है। जानें बर्फ से कैसे सुंदर त्वचा मिल सकती है। आपने खूबसूरत त्वचा पाने के लिए बाजार में मिलने वाली कई तरह क्रीम्स और घरेलू उपाय या फिर फेसपैक्स का इस्तेमाल तो ज़रूर सुना होगा। यहां तक कि कई लोग सुंदरता पाने के लिए हज़ारों खर्च कर कॉस्मेटिक या फिर लेज़र सर्जरी तक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फिज में रखी बर्फ भी आपकी त्वचा को कई मायनों में सुंदर बना सकती है। जी हां, बर्फ का एक टुकड़ा आपको

खूबसूरत स्किन दे सकता है और यहीं नहीं इससे जुड़ी कई परेशानियां को भी दूर कर सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप बर्फ से कैसे सुंदरता पा सकते हैं।

अपनाएं ये 5 उपाय

1. अगर आप सनबर्न या टैनिंग से परेशान हैं, तो कुछ दिनों तक रोज़ाना बर्फ का एक टुकड़ा त्वचा के उस हिस्से पर लगाएं। आपको जल्द ही इससे राहत मिलेगी।
2. यहां तक कि आप मेकअप करने से पहले भी चेहरे पर बर्फ रगड़ सकती हैं। इससे ये लंबे वक्त तक खराब नहीं होगा।
3. चेहरे पर ग्लो पाने के लिए रोज़ बर्फ लगाएं। अच्छे रिज़्यूल्ट के लिए संतरे या तरबूज़ के जूस को आईस ट्रे में रखकर बर्फ जमा लें और इसे चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे में निखार आएगा।
4. अगर आपके चेहरे पर एकने की वजह से रेडेनेस या फिर जलन रहती है तो बर्फ आपको इससे राहत पहुंचा सकती है। एक साफ और मुलायम कपड़े में बर्फ का टुकड़ा बांधकर पिंपल वाले हिस्से पर थोड़ी देर रखें और हटा लें। इस प्रोसेस को 4-5 बार दोहराएं।
5. अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो शहद को गुलाबजल में मिलाकर बर्फ जमा लें। इसे नियमित रूप से चेहरे पर इस्तेमाल करें। ये चेहरे से एक्सट्रा ऑयल को कंट्रोल कर इस परेशानी से राहत दिलाएंगा।

नोट : बर्फ का इस्तेमाल कभी भी त्वचा पर सीधे न करें। हमेशा किसी साफ और मुलायम कपड़े में बांध कर करें। अगर आप साइनस या स्नोफ़ीलिया जैसी समस्या है तो इसका इस्तेमाल न करें।

खूबसूरती पाने के लिए त्वचा पर ऐसे करें बर्फ का इस्तेमाल!



किया है, इनमें से 76 पूर्ण हो गया है।

पेंशन, पेयजल, स्वास्थ्य और सिंचाई

गरीब परिवारों के लिए शासन की पेंशन योजना मद्दागर साबित हो रहा है। कुलहाड़ीघाट में कुल 196 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए 8 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिसमें 111 बच्चे दर्ज हैं। इसके अलावा गर्भवती माताओं को गरम भोजन भी दिया जा रहा है। क्षेत्र में कृषि सिंचाई की जरूरत को देखते हुए निकट के सरार में ऋड़ा द्वारा सौर सामुदायिक सिंचाई योजना से 49 किसानों के 60 हेक्टेयर रक्बा में सिंचाई सम्भव हो सका है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता रही है।

कुलहाड़ीघाट एवं उनके आश्रित ग्रामों में 16 हेण्डपंप में 2 सोलर पंप के माध्यम से नलजल संचालित है। ग्राम कठवा में वाटर ए.टी.एम भी स्थापित किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा सूखा राहत के अलावा 48 किसानों को आबादी पट्टा एवं कुल 471 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा वितरित किया गया है। वहीं कृषि विभाग द्वारा उड्ढ फसल प्रदर्शन एवं 5 किसानों को सौर पंप, 15 किसानों को डीजल पंप प्रदान किया गया

है। वहीं सुराजी गांव योजना के तहत 42 किसानों को चयन किया गया है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी संचालित है।

अधोसंरचना विकास की इज़्ज़ाशक्ति

पुल, पुलिया, स्टापडेम और सड़क गांव तक पहुंची। लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक कारगार योजना साबित हुई है। यहां 442 जॉब कार्डधारी हैं। इस वर्ष 36 हजार 999 मानव दिवस सृजित किया गया। योजना अंतर्गत स्टापडेम सह पुलिया निर्माण एवं बाजार शेड का निर्माण कार्य हुआ। मनरेगा अंतर्गत भूमि सुधार, डबरी, कुंआ के साथ सुराजी गांव योजना के तहत 4.5 एकड़ में 19.79 लाख रुपये की लागत से गौठान एवं



पौनी पसारी परम्परागत व्यवसायों को नया जीवन देने की पहल

- डॉ. ओमप्रकाश ड्हरिया

पौनी पसारी का नाम सुनते ही आज के पढ़े लिखे नौजवानों को अचरज होता है लेकिन यह हमारी छत्तीसगढ़ी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा शब्द है। इसका संबंध परम्परागत रूप से व्यवसाय से जुड़े लोगों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने से था। बदलती हुई परिस्थितियों में जब गांवों ने नगरों का स्वरूप लिया तो इन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए हर घर में जाकर सुविधा देने में दिक्षित होने लगी तब उनके लिए एक व्यवस्थित बाजार की कल्पना हुई। वर्तमान समय में युवाओं को रोजगार दिलाने में यह काम आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक समय में भी इन कार्यों की महत्ता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के साथ ही व्यवसायिक और व्यापारिक दृष्टि से काफी सम्पन्न प्रदेश रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातत्व विभाग द्वारा हुए उत्खनन से यह सिद्ध होता है। महासमुंद जिले के सिरपुर में महानदी के किनारे एक सुव्यवस्थित बंदरगाह और एक बड़े व्यापारिक नगर के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहां तत्कालीन समय का व्यवस्थित

सुपरमार्केट था। यहां अनाज, लौह शिल्प, काष्ठ, कपड़े आदि का व्यापार होता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में विदेशी आर्बांटि तक योजना शुरू की गई है। इससे लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। विशेष बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में परंपरागत व्यवसाय करने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जिसके चलते बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है। कुछ लोग अपराध की ओर अग्रसर होने मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा परंपरागत पौनी-पसारी व्यवसाय को योजना बनाकर क्रियान्वित करना इस तरह के व्यवसाय से जुड़े लोगों और उनके परिवारों के उत्थान के लिए प्रशंसनीय कदम है। यह बताना उचित होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पौनी-पसारी योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत नगरीय निकायों के बाजारों में परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को जगह धुलाई और रंगाई, केश कला, लौह शिल्प काष्ठ शिल्प से जुड़े लोगों के लिए सभी नगरीय निकायों में पक्का चबूतरा और



मानसून के मौसम की सबसे ताकतवर सब्जी

खाएंगे तो कभी नहीं होंगी
ये गंभीर बीमारियां

हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी सब्जी के बारे में जिसे खाकर आप फौलाद जैसे दिखने लगेंगे। इसमें औषधि जैसे गुण भी हैं। आप हर दिन सब्जी खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी कौन सी है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी सब्जी के बारे में जिसे खाकर आप फौलाद जैसे दिखने लगेंगे। इसमें औषधि जैसे गुण भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी गुणवत्ता वाली सब्जी आखिर कब बाजार में मिलती होगी। बता दें कि कंटोला आमतौर पर मानसून के मौसम में बाजार में आता है। इसके फायदे के कारण अब इसकी मांग दुनिया भर में है। वहीं मुख्य रूप से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती होती है।

कंटोला के स्वास्थ्य लाभ

बीपी : कंटोला में मौजूद मोमोरेडीसिन तत्व एंटीऑक्सीडेंट, एंटीडायबिटीज और एंटीस्ट्रेस की तरह काम करता है। इसका सेवन करने से बीपी कंट्रोल हो जाता है।

पाचन किया : अगर आप इसकी सब्जी नहीं खाना चाहते तो अचार बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई रोगों के इलाज के लिए इसे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। यह पाचन किया को दुरुस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

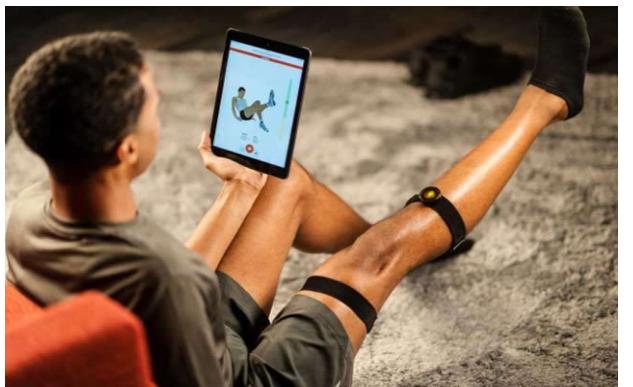
कैंसर : कंटोला में मौजूद ल्युटेन जैसे केरोटोनोइड्स विभिन्न नेत्र रोग, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर की रोकथाम में सहायक है।

सर्दी-खांसी : कंटोल में एंटी-एलर्जन और एनालजेसिक सर्दी खांसी से राहत प्रदान करने और इस रोकन में काफी सहायक है।

बेट लॉस : कंटोला में प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है जबकि कैलोरी कम मात्रा में होती है। यदि 100 ग्राम कंटोला की सब्जी का सेवन करते हैं तो 17 कैलोरी प्राप्त होती है। जिससे वजन घटाने वाले लोगों के लिए यह बेहतर विकल्प है।



के नाम से भी जाना जाता है। इसके सेवन से आप सेहतमंद



गलत एक्सरसाइज करते ही बज उठेगा अलार्म यह डिवाइस बताएगा सही तरीका

[वीणा तिवारी]

किया गया है।

व्यायाम में गलतियों से तुरंत आगाह करेगा वच्रउल रियलिटी ब्रेस्ड रीहैबिलिटेशन पर आधारित सेंसर

क्या कहा, आपको एक्सराइज करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या आप प्रतिदिन लगभग एक घंटे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिटनेस का स्तर जस का तस है? ..चिंता मत कीजिए, अब आपकी इस समस्या का समाधान चंद मिनटों में संभव होगा। चंडीगढ़

स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआइओ) के

वैज्ञानिकों ने आमजन की इस समस्या के समाधान के लिए एक विशेष प्रकार का डिवाइस बनाया है। इस उपकरण के सामने गलत एक्सरसाइज करते ही उसका अलार्म बज उठेगा और आपको आगाह कर देगा।

चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के वैज्ञानिकों ने बनाया विशेष उपकरण इतना ही नहीं यह आपको व्यायाम करने का सही तरीका भी बताएगा। सीएसआइओ के

जैव-चिकित्सकीय उपकरण विभाग (बायोमेडिकल

इंस्ट्रूमेंशन विंग) के प्रमुख वैज्ञानिकों की टीम ने इस डिवाइस को वच्रउल रियलिटी ब्रेस्ड रीहैबिलिटेशन के सिद्धांत पर बनाया है।

इसके लिए गेम प्ले का भी अॉप्शन देगा। साथ ही तस्वीर भी सामने आ जाएगी कि क्या गलती की गई है

और सही तरीका क्या है। इसे देखकर व्यक्ति सही

तरीके से एक्सरसाइज कर सकेगा।

गेम प्ले का भी है ऑप्शन

वैज्ञानिकों ने गेमिंग के रोचक अंदाज को भी इसमें शामिल किया है।

इसके लिए गेम प्ले का भी अॉप्शन बनाया गया है। जिसमें अपनी रूटीन एक्सरसाइज का गेमिंग फार्मेट में आकलन कर सकेंगे। मसनल, गलत

करने पर आपके अंक कट जाएंगे और सही करने पर स्टार प्वाइंट मिलेगा। इसे आकर्षक बनाने के लिए इसका श्रीड़ी वर्जन भी लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में उपयोगकर्ता के एक्सरसाइज का डाटा

वहीं, न्यूरो (मस्तिष्क) और मसल्स (मांसपेशियों) के बीच संतुलन से जुड़ी समस्याओं के लिए और काग्नेटिव यानी सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियों से संबंधित मरीजों की समस्याओं के लिए भी इसे डिजाइन



सकेगा। प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में इस योजना के जरिए जन सामान्य और युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आगामी दो वर्ष में इस योजना के लिए 73 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। प्राचीन सभ्यता में भी पौनी-पसारी का व्यवसाय काफी सुदृढ़ था। तत्कालीन समय में लोग पढ़े-लिखे नहीं होते थे। वे परम्परागत रूप से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले और जीवकोपार्जन के लिए आवश्यक चीजों का स्थानीय हाट-बाजारों से अदला-बदली कर या प्रचलित मुद्रा देकर क्रय करते थे। चूंकि प्राचीन सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अतः नगरीय हाट-बाजारों में उपयोग की आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती रही होंगी। वहीं परम्परागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार के लिए इधर-ऊधर भटकना नहीं पड़ता था। प्राचीन ग्रंथों में इस तथ्य का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि उन दिनों व्यक्तिगत स्वामित्व वाले निजी और पारिवारिक व्यवसायों में ज्यादातर लोग जुड़े थे। भारतीय धर्म शास्त्रों में भी प्राचीन समाज की आर्थिकी का विश्लेषण किया गया है। लोगों ने सामूहिक हितों के लिए संगठित व्यापार अपनाकर अपनी सूझ-बूझ का परिचय दिया था। इसी कारण वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से काफी समृद्ध थे। सासाहिक बाजार एवं पौनी-पसारी स्थानीय छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। सासाहिक बाजारों के माध्यम से जहां एक ओर स्थानीय जनता अपने जीवन-यापन के लिए आवश्यक सामान की खरीदी करते थे, वहीं पौनी-पसारी के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय की आवश्यकताओं तथा सेवाओं की पूर्ति भी सुनिश्चित की जाती थी, जिसमें स्थानीय परंपरागत व्यवसायों जैसे-लोहे से संबंधित कार्यों, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते-चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी-भाजी उत्पादन, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, कंबल, मूर्तियां बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन

सामग्री, बांस का टोकना, सूपा, केशकर्तन, दोना-पतल, चटाई तैयार करना तथा आभूषण एवं सौंदर्य सामग्री इत्यादि का व्यवसाय तथा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परम्परा को भी सहेजा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना प्रारंभ करने जा रही है इस योजना के तहत नगरीय निकायों के बाजारों में जगह उपलब्ध कराए जाने के साथ ही व्यवसाय की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस योजना से लगभग 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पौनी पसारी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के जरिए सभी 168 नगरीय निकायों में जनसामान्य और युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस योजना के तहत लोहारी, कुम्हारी, कोषा, बंसोड़ आदि का परंपरागत व्यवसाय करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरान्त सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत 'पौनी-पसारी' व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी। योजना का क्रियान्वयन शहर के प्रमुख स्थलों को केन्द्र बिन्दु बनाकर किया जा रहा है। 'पौनी-पसारी' योजना के अंतर्गत मानक प्राकलन एवं ड्राइंग तैयार की गई है। प्रत्येक नगर पंचायत हेतु 01, नगर पालिका हेतु 02, नगर निगमों (रायपुर को छोड़कर) हेतु 04 एवं नगर निगम रायपुर के लिए 08 पौनी पसारी बाजार की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। प्रति बाजार निर्माण के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। पौनी पसारी बाजार शासकीय-निकाय की भूमि पर स्थापित किया जा सकेगा। पौनी पसारी योजना के तहत ऐसे परंपरागत व्यवसायों जैसे-लोहे से संबंधित कार्यों, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते-चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी-भाजी उत्पादन, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, कंबल, मूर्तियां बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन



'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' के संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करेंगे

[छगन लोन्हरे]

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने लगभग 08 माह के कार्यकाल में एक विशेष पहचान स्थापित की है। (इसमें ढाई से तीन माह तक लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचरण सहित प्रभावशील रही) चाहे वह किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ हो, या 2500 रूपये प्रति किंटल की दर से वाजिब दाम देकर समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन शामिल है। ऋण माफी योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों के 11 हजार करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज माफ किया गया। प्रदेश की मेहनतकश किसानों के पसीने का सम्मान करते हुए इस तरह उन्होंने किसानों से किया गया वादा पहले निभाया। मुख्यमंत्री द्वारा पदभार ग्रहण करते ही 02 घंटे के भीतर ही किसानों की कर्ज माफ की कार्रवाई पूरी की। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण छत्तीसगढ़ सरकार की कल्याणकारी सोच से बाकिफ है। आम लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रदेश सरकार द्वारा छोटे भू-खण्ड के खरीद-बिक्री पर रोक हटने से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। जिसके कारण लगभग 60 हजार लोगों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री करायी। मुख्यमंत्री का मानना है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प हम सब मिलकर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने तीजा पर्व, हरेली, माता कर्मा जयंती, छठ पूजा एवं विश्व आदिवासी दिवस पर नये सार्वजनिक अवकाश घोषित कर एक ठेठ छत्तीसगढ़िया की पहचान दिलाई। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व हरेली बहुत ही धूम-धाम से मनाया गया। स्कूल-कॉलेजों में हजारों शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, कन्या विवाह योजना की सहायता राशि 15 हजार रूपये से

बढ़ाकर 25 हजार रूपये की गई। प्रदेश के तेंदूपता संग्रहण दर 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति मानक बोरा की गई। बस्तर के लोहांडीगुड़ा में उद्योग कंपनी द्वारा अधिगृहित की गई जमीन की वापसी, इन्द्रावती विकास प्राधिकरण का गठन, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ जैसे अनेक जनहितकारी फैसलों से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। दिव्यांगजनों के विवाह हेतु उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र का प्रोत्साहन राशि प्रति जोड़े 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 01 लाख रूपये की गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में इजाफा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के नगरनार प्लांट में रूप सी तथा डी की भर्ती परीक्षा देंतेवाड़ा में कराने को लेकर एनएमडीसी को राजी कराया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गौरेला-पेण्डाऊ मारवाही के नाम से एक नए जिले के गठन की घोषणा की। इसके अलावा प्रदेश में 25 नई तहसीलों की गठन की घोषणा की। प्रदेश के सभी पंचायतों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे प्रथम चरण में 20 हजार पंचायतों से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्लब का उद्देश्य युवाओं को छत्तीसगढ़ी परम्परा व संस्कृति को सहजने के लिए आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना है, एक तरह से उन्होंने युवाओं का दिल जीता। मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी गरीब के आशियानों को नहीं उजाड़ने का फैसला किया गया है। इस निर्णय से 19 नवम्बर 2018 के पूर्व बने किसी भी मकान को नहीं हटाया जाएगा और उन्हें पट्टा वितरण की कार्यवाही की जाएगी। इससे प्रदेश के औद्योगिक शहरों सहित प्रदेश में निवासरत लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा निर्णय

कहा भी जाता है 'दिन का एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है।' न्यूमोकोक्स फैलता है निमोनिया शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन को मुख्य रूप से स्ट्रेपोकोक्स निमोनिया पर केंद्रित किया है। यह एक जीवाणु है, जिसे न्यूमोकोक्स कहा जाता है। यह निमोनिया का सबसे आम जीवाणु है, लेकिन यह मेनिंजाइटिस और गंभीर सेप्सिस का कारक भी हो सकता है। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधकता कम हो तो बैक्टीरिया शरीर को बीमार बना देते हैं।

सेब खाने से...

सेब फल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसमें पाए जाने वाले पॉलीफेनोल और फ्लेवोनोइड्स दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा, यह शरीर के लिए आवश्यक मिनेरल्स, और पोटेशियम तत्वों का बेहतरीन स्रोत है। दिन में एक बार सेब का जूस पीने से हृदय के लिए सुचारू रूप से काम करने लगता है। इसका जूस दमा रोगियों को लाभ पहुंचाता है। इसमें दमे के अटैक को रोकने की क्षमता होती है। इसमें पाया जाने वाला फ्लेवोनोइड्स फेफड़ों को ताकतवर बनाता है। सेब में मौजूद अल्कालिनिटी लीवर के शरीर के शोधन में मदद करता है। इसकी बाहरी परत में मौजूद पेकिटन से पाचन-तंत्र को दुरुस्त करती है।

सेब खाने के फायदे

सेब में पेकिटन जैसे फायदेमंद फाइबर्स पाए जाते हैं। हर रोज एक सेब खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह और दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। सेब खाने के ये नौ ऐसे फायदे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। स्वस्थ और सफेद दांतों के लिए। बढ़ती उम्र की वजह से मस्तिष्क पर

पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए। सेब में भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर्स पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होते हैं। सेब का सेवन करने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। सेब के नियमित सेवन से टाइप-2 मधुमेह होने का खतरा कम हो जाता है।

सेब का सेवन करना दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। सेब के नियमित सेवन से कब्ज की समस्या नहीं होती है। वजन को नियंत्रित करने के लिए भी सेब का नियमित इस्तेमाल फायदेमंद होता है।

सेब के नियमित इस्तेमाल से शरीर के भीतर मौजूद कई विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।

सेब खाने से क्या नुकसान होता है

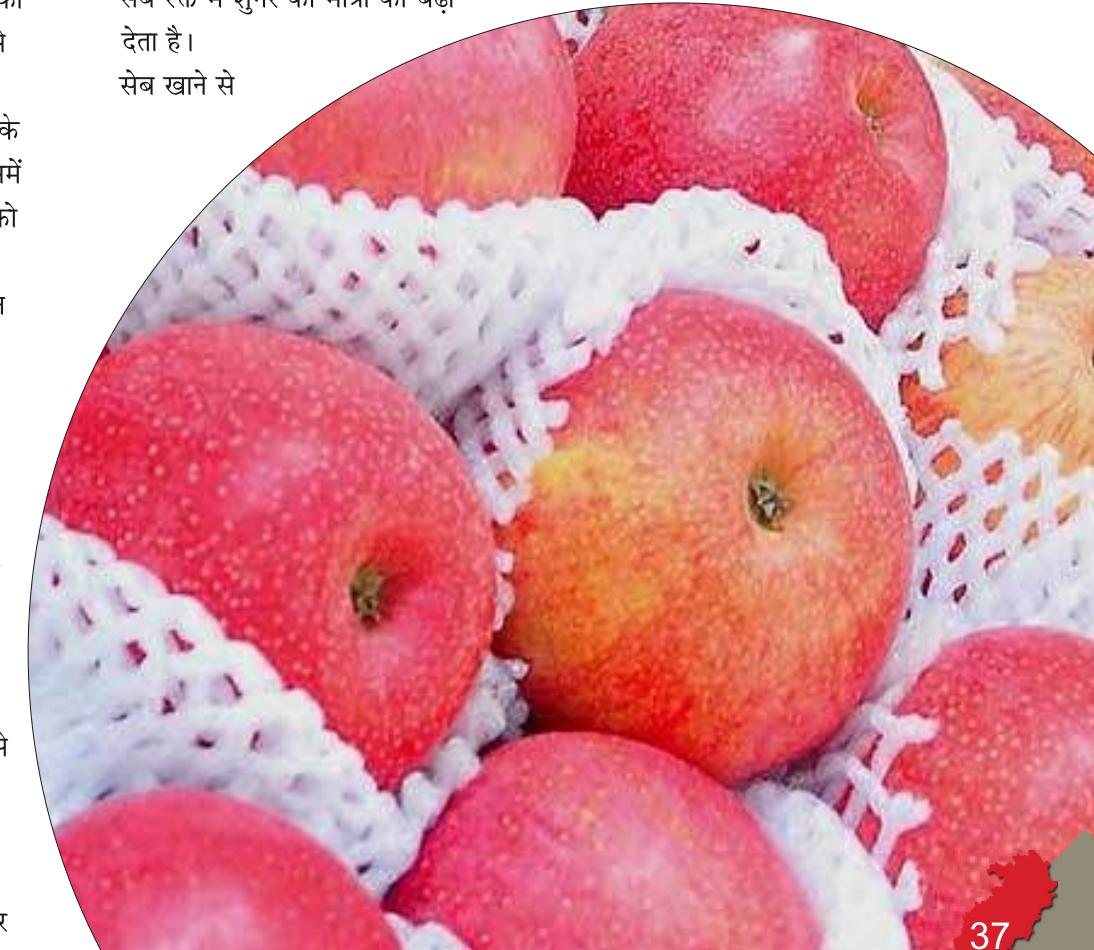
सेब रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। सेब खाने से

एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाते हैं। सेब के बीज से हानि होती है, इसमें साइनाइट पायी जाती है। कैलोरीज और शुगर की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इससे वजन बढ़ जाता है। अम्लीय (एसिडिक) होने के कारण सेब दातों को नुकसान पहुंचाता है।

सेब के नुकसान से कैसे बचे

यदि आप सेब से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप सेब को सही समय पर और सही मात्रा में खाएं। आप हर रोज सुबह या दोपहर में सेब खाएं।

सेब के जूस का सेवन करें। सेब खाने के बाद दांत साफ़ करें। सेब को रात में ना खाएं। एक दिन में एक सेब से ज्यादा सेब ना खाएं। सेब के बीज का सेवन ना करें।





निमोनिया सहित कई बीमारियों से दूर रखने वाला सेब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है

शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन को मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोक्स निमोनिया पर केंद्रित किया है। यह एक जीवाणु है जिसे न्यूमोकोक्स कहा जाता है। सेब जैसा फल जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वे हमारी एंटी-बैक्टीरियल इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें

निमोनिया से बचा सकते हैं। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इम्यून सिस्टम को सेब को साफ कर कीटाणुरहित भी किया जाता है। इन दिनों सेब खूब मिलता है, इसलिए दिन में एक सेब खाइए और खुद को सेहतमंद रखिए। यह अध्ययन नेचर कम्प्यूनिकेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

स्कीडन की उमिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्वकर्ता नेल्सन गेकारा ने कहा कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हराने के लिए निमोनिया का बैक्टीरिया हाइड्रोजेन पेरोक्साइड का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया आग से लड़ रहे हैं। हालांकि इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा शरीर स्वयं ही हाइड्रोजेन पेरोक्साइड का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि ज्यादातर बैक्टीरिया शरीर की रोग प्रतिरोधकता से लड़ने के लिए एक जैसे ही पदार्थों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजेन पेरोक्साइड को बेअसर करने की सर्वाधिक क्षमता विटामिन सी में होती है और फलों में विटामिन सी पर्यास मात्रा में पाया जाता है। ये एंटी-बैक्टीरियल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसलिए



बदले-बदले से लग रहे गांव

[चतुर्वेदी चौधरी]

कृषि विभाग द्वारा वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए वर्मीबैड तथा नाडेप टाका बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जिले के चयनित नालों पर जल संरचनाओं के लिए स्टापडेम सहित अन्य संरचनाओं को विकसित किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले के खासकर नदियों के किनारे वाले चयनित गांवों में बाड़ी विकास के काम किए जा रहे हैं। इन गांवों में हितग्राहियों का चयन बाड़ी विकास के लिए किया गया है। राज्य सरकार की इस मत्वाकांक्षी योजना के मूर्त रूप लेने से गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहाँ पर जैविक एवं कम्पोस्ट खाद के उत्पादन से कृषि उत्पादकता में काफी इजाफा होगा। इससे जिले में जैविक खेती को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।



नागलगुण्डा, मराईगुड़ा (राजस्व), कांकेरलंका और पोलमपल्ली ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत गोठान बनाए गए हैं। इन ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में बनाए गए गोठानों में गांव के पशु पालकों द्वारा अपने पशुओं को स्वःस्फूर्त लाया जा रहा है। यहाँ पर पशुओं को चारा, पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। गांव की अर्थव्यवस्था में हमेशा से ही गोवंशी पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम जानते हैं कि गांव ग्रामीण, किसान और पशु हमेशा से ही एक दूसरे के पर आश्रित रहे हैं, समय के साथ इनके बीच सरोकार थोड़ा कम हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ओर सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार की नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना अब संजीवनी का काम करेगी।

सुकमा जिले के विभिन्न विकास खण्डों की 23 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में गोठान बनाए गए हैं, गोठानों ने तेजी से आकर लिया है। उल्लेखनीय है कि जिले के कलेक्टर श्री चंदन कुमार के कुशल निर्देशन और उनके द्वारा कार्यों की लगातार मानीटरिंग और जिला पंचायत की मुख्य पालन अधिकारी सुश्री ऋष्णा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में विभागों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। जिले के गांव नेतनार, केरलापाल, निलावरम, कोरा, गोंगला, बुड़दी, कांजीपानी, पाकेला, चिपुरपाल, राजागुण्डा, सौतनार, बिरसठपाल, गुम्मा, किकिरपाल, रोकेल, मिसमा, सामसट्टी, दुब्बाटीया,



वर्ल्ड बैंक करेगा 'नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी' योजना में मदद

वर्ल्ड बैंक छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना 'नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी विकास योजना' के लिए मदद देगा। रायपुर के प्रवास पर आए वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड श्री जुनैद कमाल अहमद ने आज सवेरे यहां मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। श्री अहमद ने मुख्यमंत्री श्री बघेल और इस अवसर पर उपस्थित कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि की दृष्टि के कम विकसित क्षेत्रों में नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन में बढ़िया के उपायों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने श्री अहमद को प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए प्रारम्भ की गई सुराजी गांव योजना 'नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी विकास योजना' की विस्तृत जानकारी दी। श्री बघेल ने बताया कि इस योजना में ग्रामीणों का स्वतःस्फूर्त सहयोग मिल रहा है।

श्री जुनैद ने खेती-किसानी की प्रगति के लिए शुरू की गई इस योजना की सराहना करते हुए, छत्तीसगढ़ में 'नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी विकास योजना', कृषि क्षेत्र के विकास और कृषि आधारभूत संरचनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हर-संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री बघेल ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड श्री जुनैद को बताया कि नरवा योजना में नदी-नालों को रिचार्ज करने का कार्य किया जा रहा है। गरवा के माध्यम से पशुधन विकास के कार्य किये जा रहे हैं। जिसमें गांवों में गौठान और चारागाह विकसित किये जा रहे हैं। गौठानों को पशुओं के डे-केयर सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पशुओं के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही पशुओं के गोबर से घुरवा में कम्पोस्ट और वर्मी खाद तथा बायो गैस का उत्पादन किया जाएगा। गौठानों में पशु नस्ल सुधार के कार्यों के साथ दुग्ध उत्पादन के लिए भी कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्य से गांव के महिला स्वसहायता समूहों और युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इस योजना से पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों को धेरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसानों को जैविक खाद उपलब्ध होगी, कृषि लागत कम होगी, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दो हजार गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है जिनमें से लगभग डेढ़ हजार गौठान बन गए हैं। बाड़ी योजना में किसानों के घरों की बाड़ी में सब्जियों और मौसमी फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा।

नरवा से जल संरक्षण को मिला बढ़ावा

वर्षा की कमी के बावजूद, नालों में बढ़ा पानी का संग्रहण सुराजी योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के माध्यम से जल संरक्षण और जल संवर्धन के कार्यों का प्रभाव दिखने लगा है। रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड में छोटे-छोटे नालों के प्रारंभिक बिन्दु से नदी के मिलने तक जल संरक्षण के अनेक कार्यों से इन नालों में वर्षा की कमी के बावजूद पानी की उपलब्धता बढ़ी है। भू-जल का रिचार्ज हो रहा है, नालों में पानी बढ़ने से समीप के किसान भी उत्साहित हैं। धरसींवा विकासखण्ड में वर्षा शुरू होने के पहले ही जनजागरूकता का कार्य प्रारंभ किया गया। स्कूली बच्चों, कालेज के विद्यार्थियों, नेहरू युवा केन्द्र के वालिन्यिर्यस तथा नागरिकों के सहयोग से जल को सहेजने और इसका सटुपयोग करने की समझाईश दी गई।

शासकीय भवनों जैसे कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, पंचायत भवनों, प्रार्थना शेष आदि में जल संचयन स्ट्रक्चर स्थापित करने के साथ शहरी क्षेत्रों में निजी आवासों और



साउथ इंडियन थाली में कैसे आई बिहार की लिट्टी

[प्रियंका मेहता दुबे]

अप्पम के प्लेट में लिट्टी बनाकर पारूल ने बेहतरीन हेल्दी एक्सप्रेसीमेंट किया है। इसके गुण को और बढ़ाने के लिए इसमें पनीर मिलाया गया है। फिर बन गया लाजवाब लिट्टी चोखा।

गुरुग्राम निवासी पारूल शुक्ला एम्बीए करने के बाद कॉर्पोरेट कंपनी में प्रतिष्ठित पद पर नौकरी कर रही थीं। यह अलग बात है कि बचपन से ही उन्हें खाने-खिलाने का कुछ ऐसा शौक था कि जब तक वह किसी डिश पर प्रयोग कर उसे नया रूप नहीं दे देती थीं, उनका किसी और काम में मन ही नहीं लगता था।

कुछ समय तो ऐसा चला, लेकिन शौक बराबर उन्हें यह सब याद दिलाता रहा, लिहाजा उन्होंने नौकरी छोड़ दी और रेस्तरां चलाने लगीं। अब वह होम शेफ और फूड ब्लॉगर हैं। ब्लॉग 'हंग्री-ऑबर्जर्वर' के तहत वह रोजाना फूड प्रेमियों को नई-नई डिशेज से रूबरू करवाती हैं।

वजन बढ़ाने के कारण उन्होंने जायकों को स्वास्थ्यवर्द्धक बनाने की दिशा में शोध व प्रयोग किए और अब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही डिशेज तैयार करती हैं। इसमें खास है ओट्स व चिया सीड़ तैयार की खीर। कभी सामान्य भोजन में शामिल न

थाली में बिहार की लिट्टी। जी हाँ, अप्पम के प्लेट में लिट्टी बनाकर पारूल ने बेहतरीन हेल्दी एक्सप्रेसीमेंट किया है। इसके गुण को और बढ़ाने के लिए इसमें पनीर मिलाया गया है। फिर बन गया लाजवाब लिट्टी चोखा।

गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन व धी मिलाकर उसे अच्छी तरह गूँथ लिया जाता है। फिर अदरक-लहसुन पेस्ट, नमक, गरम मसाला, हरा धनिया और कहूँकस किए हुए पनीर को अच्छी तरह मिलाकर इसे भरा जाता है। उसके बाद अप्पम के सांचे में डालकर उसे पकाया जाता है। इसके साथ पके हुए टमाटर, कटे प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक व कच्ची धानी सरसों तेल की कुछ बूंदें डालकर मसल कर सलाद तैयार किया जाता है। पारूल के मुताबिक यह टेस्टी मील कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई होती है। जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद उपयुक्त है।

ओट्स व चिया सीड़ की खीर

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अक्सर मीठा खाने से परहेज करते हैं। ऐसे में पारूल डेजर्ट में भी हेल्दी विकल्प दे रही हैं। गुड़-मखाने और इमली के प्रयोग से वह डेजर्ट तैयार करती हैं। इसमें खास है ओट्स व चिया सीड़ तैयार की खीर। कभी सामान्य भोजन में शामिल न

किए जाने वाले चिया सीड़ को बजन घटाने से लेकर विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लिहाजा पारूल ने इसे डेजर्ट में शामिल कर लिया है और ओट्स के साथ चिया सीड़ को दूध में उबालकर लजीज खीर बनाती है। पारूल कहती हैं कि प्रोटीन, कैल्शियम और फैट का सही कॉम्बीनेशन इस डिश को हेल्दी बनाता है।

सब्जियों से गुणों में लिपटा रंग-बिरंगा रैप

गेहूं के आटे में पालक या चुकंदर मिलाकर गूँथने पर अलग-अलग रंग का आटा तैयार हो जाता है। इससे रैप की कर्वंग तैयार होती है। इसमें भरने के लिए शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम और प्याज को कड़ाही में हल्का भूनकर उसमें चिली सॉस, सिरका, टोमैटो सॉस और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है।

आटे को रोटी के आकार में बेलने के बाद उसमें फिलिंग भरकर ग्रिल किया जाता है। यह व्यंजन खास तौर पर बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं। इस तरह रंगबिंगे रैप में लिपटी सब्जियों को बेचाव से खाएंगे।

प्रतिदिन 9000 हाथियों के बराबर पैदा होता है प्लास्टिक कचरा, इसलिए पीएम ने की अपील

वर्ष 1950 से अबतक वैश्विक स्तर पर 8.3 से 9 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है जो कचरे के चार से अधिक माउंट एवरेस्ट के बराबर है। आज भारत समेत दुनिया के तमाम देश प्लास्टिक के कचरे से परेशान हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया है। वर्ष 1950 से अबतक वैश्विक स्तर पर 8.3 से 9 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है, जो कचरे के चार से अधिक माउंट एवरेस्ट के बराबर है। अब तक निर्मित कुल प्लास्टिक का लगभग 44 फीसद वर्ष 2000 के बाद बनाया गया है। वहीं भारत में प्रतिदिन 9 हजार एशियाई हाथियों के बजन जितना 25,940 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। फिर भी, भारतीय दुनिया के सबसे कम प्लास्टिक उपभोक्ताओं में शामिल हैं। एक भारतीय एक वर्ष में औसतन 11 किग्रा प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है।

पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक

उत्पादित प्लास्टिक का लगभग 40 फीसद पैकेजिंग के इस्तेमाल में आता है, जिसे एक बार उपयोग किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। 1950 के बाद से उत्पादित सभी प्लास्टिक का 79 फीसद पर्यावरण में अभी भी मौजूद है।

कचरा घर बना समृद्ध

जॉर्जिया विश्विद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक 41 लाख टन से 1.27 करोड़ टन के बीच प्लास्टिक हर साल समुद्र में प्रवेश करता है, जो 2025 तक दोगुना होने की उम्मीद है।

बेहद हानिकारक

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर साल लगभग 5 ट्रिलियन प्लास्टिक की थैलियां दुनिया भर में उपयोग की जाती हैं। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण, समुद्र और धरती पर रहने वाले जीवों के लिए बेहद हानिकारक हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश 2002 में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था। कई अफ्रीकी देशों ने अपेक्षाकृत कम अपशिष्ट-संग्रह और रीसाइकिलिंग दरों के लिए जगह

बनाई है। अमेरिका ने अभी तक प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, हालांकि उसके कुछ राज्यों ने स्वयं ही थैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है।

भारत ने छेड़ी जंग

20 अगस्त को भारतीय संसद ने कहा कि वह परिसर में प्लास्टिक की बस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। 2 अक्टूबर से भारतीय रेलवे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ये दोनों घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के कुछ दिनों बाद आई हैं, जिसमें उन्होंने नागरिकों से प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने का आग्रह किया था। प्लास्टिक के खिलाफ भारत ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सीपीसीबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन का आकलन करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट अंतिम बार 2017-18 के लिए प्रकाशित की गई थी। 2018 में इसके नियमों में संशोधन किया गया था। 2017-18 में केवल 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीपीसीबी को सौंपी थी। इन 14 में से उत्तर प्रदेश में हर साल 2.06 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। यहां पर प्लास्टिक निर्माण और रिसाइकिल की 16 अपंजीकृत इकाइयां भी थीं। वहीं गुजरात में 2.69 लाख टन प्रति वर्ष प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ।



नल के पानी में प्लास्टिक

देश	प्लास्टिक फाइबर प्रति 500 से युक्त नल का पानी (प्रतिशत में)	मिली में औसत फाइबर
लेबनान	98	4.5
अमेरिका	94.4	4.8
भारत	82.4	4
झावाड़ार	79.2	2.2
इंडोनेशिया	76.2	1.9
यूरोप	72.2	1.9



राज्यों में प्लास्टिक कचरा

राज्य	प्लास्टिक कचरा (टन प्रति वर्ष)	निर्माण/रिसाइकिल इकाई
उत्तरप्रदेश	2.06लाख	133
गुजरात	2.69 लाख	882
मध्यप्रदेश	0.61लाख	71
पंजाब	0.54 लाख	144
नगांड़े	0.14लाख	6
ओडिशा	0.12लाख	20



वृक्षारोपण का कार्य किया गया। विकासखण्ड में इस वर्षा अभी तक 636 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत वर्षा 965 मिलीमीटर की मात्र 65.9 प्रतिशत है। इसके बावजूद जिन नालों को साफ किया गया है, वहां के नाले पानी से भरपूर नजर आ रहे हैं और नाले के समीप के किसान अब इस पानी का उपयोग अपनी खेती -किसानी के लिए भी कर रहे हैं। ग्राम मलौद के संरपंच श्री श्रवण कुमार देवांगन ने बताया कि गांव में तालाब का गहरीकरण किया गया, दस-बारह एकड़ में वृक्षारोपण किया गया, नालों को साफ किया गया, तीन-चार बंधान बनाए गये इससे अब नाले पानी से लबालब हैं। भटांव के संरपंच श्री महेश डहरिया ने बताया कि गांव के पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल आदि में वाटर रिचार्जिंग का कार्य किया गया है। मटिया बांधा नाला के समीप रहने वाले किसान श्री ताप्रध्वज वर्मा, देवनारायण वर्मा, धनारू पारधी, चन्द्रशेखर साहू, संतलाल यादव, लक्ष्मीनारायण ठाकुर इस पहल से काफी उत्साहित हैं।

आजीविका गतिविधि का नया केन्द्र बना गौठान

11 गौठान क्षेत्र के महिला समूहों को प्रशिक्षण के जरिए सिखाए जा रहे हैं जैविक दवाई





गौठान से गोबर, गोबर से बनेगा जैविक खाद व दवाईयां

बने नये गौठान आजीविका गतिविधि केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। गरियाबांद जिले के ग्राम पारागांव, सढ़ौली, फुलकरा और मालगांव में महिला समूहों द्वारा गौठान के एकत्र किये हुए गोबर और गौ-मूत्र से नये उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं और एक नये आय जनित गतिविधि का सृजन कर रहे हैं। गौठान के गोबर से कंडे बनाने का प्रशिक्षण ले चुकी श्रीमती गंगा देवी और पार्वती ने बताया कि प्रशिक्षण से हमें एक नया अवसर मिला है। अब हम गोबर से नये वस्तुओं का निर्माण करेंगे और बाजार में बेचेंगे एवं इससे हमारी आय भी बढ़ेगी।

जिले में नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत बिहान द्वारा गौठान ग्राम पंचायतों में गौठान से प्राप्त गोबर व गौमूत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की जैविक खाद व दवाईयां निर्माण करने का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। यह जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं आजीविका संवर्धन के लिए उपयुक्त होगा। प्रशिक्षण में जैविक खाद नाडेप खाद, वर्मी कम्पोस्ट, घनाजीवामृत, द्रव जीवामृत, गोबरखाद, पंचगब्य खाद बनाने की विधि बताया जायेगा। जिसमें गौठान से प्राप्त गोबर, गौमूत्र एवं सूखा पत्ता, हरा पत्ता, दीमक मिट्टी, गुड़, बेशन, दुध, धी, केला पका हुआ, नरियल पानी, दही, महुआ दारू, सल्फी



का उपयोग किया जायेगा। साथ ही गांव में उपलब्ध निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, बेशरम पत्ती की दवाई, खट्टा मट्टा, बेलपत्ती की दवाई, हरी मिर्च लहसून की दवाई, हण्डी की दवाई, नींगुर पत्ती की दवाई, अण्डा नीबू की दवाई, दूध सोठ की दवाई, तुलसी पत्ती की जैविक दवाई बनाया जाएगा। जिसमें स्थानीय स्तर पर प्राप्त गौमूत्र, गोबर, नीम पत्ता, सीता पत्ता, धतुरा पत्ता, करंज पत्ता, बेल पत्ता, जाम पत्ता, नींगुर पत्ता, बेशरम पत्ता, फुडहड़ पत्ता, तम्बाकू, लहसून, हरी मिर्च, तुलसी पत्ता, मही, मिट्टी तेल, कच्चा दूध, सोंठ, सूखा मिर्च का उपयोग किया जावेगा। प्रशिक्षण में गरियाबांद के 11 गौठान क्षेत्र के समूह की महिलाओं का चयन किया गया है। जिला का एक सशक्त माध्यम बनेगा। गोबर एवं गौमूत्र के उपयोग से ही प्रत्येक गौठानों में 4-5 व्यक्तियों को वर्ष भर आजीविका प्राप्त होगा।

गौठान के गोबर से बनेगा जैविक खाद

इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है। देश के 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसके प्रयोग पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध है। इसके बावजूद आज भी रोजाना 10 मीट्रिक टन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल केवल शहरी इलाकों में हो रहा है। यह तो केवल आंकड़े भर हैं, जबकि हालात इससे कहीं अधिक बदतर हैं और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल देश के बड़े हिस्से में धड़ल्हे से जारी है। उस पर कोई अंकुश नहीं है। इसका बड़ा और अहम कारण यह है कि यह सस्ता, सर्वसुलभ और बहु उपयोगी है।

हर्बल प्लास्टिक इसका विकल्प

असल में प्लास्टिक अब जीवन का हिस्सा बन चुका है। घर-बाहर-बाजार इससे कुछ भी अद्यता नहीं है। एक तरह से इंसान इस पर निर्भर है। यही अहम बजह है कि लंबे समय से की जा रहीं लाख कोशिशों के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग सका है। हालात यह हैं कि दिनोंदिन इसके सामानों का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। खेद की बात यह कि इसका अभी तक कोई भरोसेमंद विकल्प भी नहीं ढूँढ़ा जा सका है। वैसे वनस्पतियों से तैयार हर्बल प्लास्टिक इसका किस सीमा तक विकल्प बन पाएगा, यह भविष्य के गर्भ में है।

प्लास्टिक के उत्पादन पर लगाएं अंकुश

इसमें दो राय नहीं कि हम लोग ही इसके जनक हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि इंसान प्लास्टिक रहित दुनिया के बारे में विचार करें। यदि समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा को कम करना है तो हम इस धरती पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। उसके उत्पादन पर अंकुश लगाएं। निस्तारण की ताल्कलिक उचित व्यवस्था करें। यह जान लें कि समुद्र का प्रदूषण हमारी धरती के प्रदूषण का ही एक हिस्सा है, पर धरती के प्रदूषण से भी अधिक यह समुद्री प्रदूषण खतरनाक साबित हो सकता है। इसे रोक पाना तभी संभव है जब धरती का प्रदूषण कम करने में हमें कामयाबी मिले। सही मायने में यह पूरा मामला प्रदूषण के कारकों को खत्म करने का है। इसमें एक महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है। समुद्र का प्रदूषण असल में हमारी जीवनशैली का ही नतीजा है। धरती पर जितना प्लास्टिक कम होगा, सागर में भी प्रदूषण उतना ही कम होगा।

[अध्यक्ष, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा समिति]



चौंकाने वाला खुलासा

सब कुछ हो रहा दूषित, हर हफ्ते पांच ग्राम प्लास्टिक निगल रहे हैं आप

दुनियाभर में बनने वाले प्लास्टिक का 75 फीसद इसका कचरा बन जाता है और लगभग 87 फीसद हिस्सा पर्यावरण में मिल जाता है। यह प्लास्टिक जल जमीन सब कुछ दूषित कर रहा है। पढ़ें रिपोर्ट...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ दो अक्टूबर से एक 'नया जन-आंदोलन' शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने 'मन की बात' में कहा कि जब देश राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती मना रहा है, तब ऐसे में 'हम प्लास्टिक के खिलाफ एक नया जन-आंदोलन आरंभ करेंगे।'

प्लास्टिक की प्रदूषण वर्तमान में एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को हो रहा नुकसान वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय शोध और सरकारी रिपोर्टों का विषय रहा है। इनसे पता चलता है कि दुनियाभर में बनने वाले प्लास्टिक का 75 फीसद इसका कचरा बन जाता है और लगभग 87 फीसद हिस्सा पर्यावरण में मिल जाता है।

हर व्यक्ति औसतन पांच ग्राम प्लास्टिक निगल रहा आँस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल द्वारा किया गया अध्ययन इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक सप्ताह में एक व्यक्ति औसतन पांच ग्राम प्लास्टिक निगल रहा है। यानी किसी न किसी माध्यम से यह नुकसानदेह चीज उसके शरीर में पहुंच रही है। अध्ययन के अनुसार प्लास्टिक कचरे का एक तिहाई से अधिक हिस्सा प्रकृति में मिल जाता है, विशेष रूप से पानी में जो शरीर में प्लास्टिक पहुंचाने का सबसे बड़ा स्रोत है। अध्ययन के मुताबिक, नल के पानी में प्लास्टिक फाइबर पाए जाने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां 82.4 फीसद तक प्लास्टिक फाइबर पाया जाता है। मतलब प्रति 500 मिली में चार प्लास्टिक फाइबर।

सीपीसीबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन का आकलन करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट अंतिम बार 2017-18 के लिए प्रकाशित की गई थी। 2018 में इसके नियमों में संशोधन किया गया था। 2017-18 में केवल 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीपीसीबी को सौंपी थी। इन 14 में से उत्तर प्रदेश में हर साल 2.06 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। यहां पर प्लास्टिक निर्माण और रिसाइकिल की 16 अपंजीकृत इकाइयां भी थीं। वहां गुजरात में 2.69 लाख टन प्रति वर्ष प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ।



क्या संभव है प्लास्टिक से मुक्ति और कितनी कारगर होगी हर्बल प्लास्टिक

[ज्ञानेंद्र रावत]

समुद्र का प्रदूषण असल में हमारी जीवनशैली का ही नतीजा है। धरती पर जितना प्लास्टिक कम होगा सागर में भी प्रदूषण उतना ही कम होगा।

प्लास्टिक का सवाल समूचे विश्व के लिए अहम बना हुआ है। यह समस्या हमारे यहाँ ज्यादा गंभीर है। देश में जारी स्वच्छता अभियान के बावजूद प्लास्टिक युक्त कचरे से गांव, कस्बा, नगर, महानगर, राज्यों की राजधानियाँ और देश की राजधानी तक अछूती नहीं हैं। इसकी चपेट में सागर और महासागर भी आने से नहीं बच सके हैं। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जानवरों के लिए तो काल बन चुका है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस बाबत न नगर वासी और न स्थानीय निकाय गंभीर हैं। इस कचरे के बोझ तले पृथ्वी इतनी दब चुकी है कि अब उसके लिए सांस लेना दूभर हो गया है।

प्लास्टिक कचरे की तादाद में बढ़ोतरी

बीते 65 सालों में मानव ने तकरीब 8.3 अरब मीट्रिक टन से भी अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया है। 1950 में प्लास्टिक का उत्पादन दुनिया में तकरीब 20 लाख मीट्रिक टन था जो 2015 में बढ़कर तकरीब 40 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। प्लास्टिक



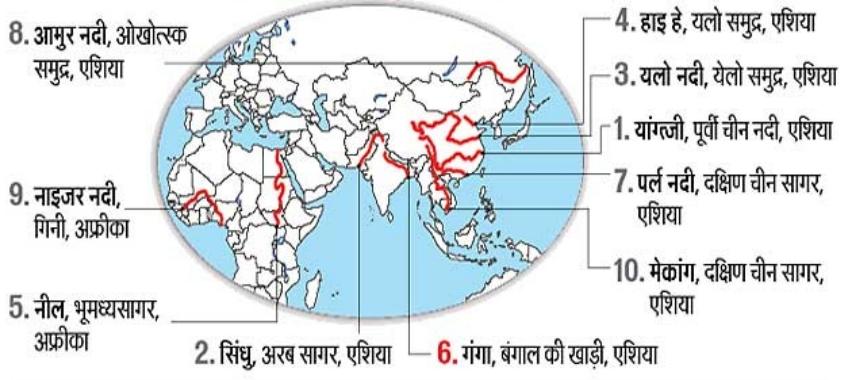
कचरा दुनिया में जगह-जगह बने लैंडफिल पर पड़ा नजर आएगा। यह स्थिति बहुत ही भयावह होगी और पर्यावरण के लिए खतरनाक होगी। मानव जीवन पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी आशंका से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

पॉलिथीन मिक्स कूड़ा जलाना

नुकसानदेह

कचरे की तादाद में बढ़ोतरी की यदि यही रफ्तार रही तो 2050 में 12 अरब मीट्रिक टन

दस सर्वाधिक प्रदूषक नदियाँ



8.3 अरब मीट्रिक
टन : अब तक पैदा
हुआ कुल प्लास्टिक

6.3 अरब मीट्रिक
टन : प्लास्टिक का
कचरा

2.36 लाख टन : समुद्र
में मौजूद प्लास्टिक कचरा (5
लाख करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े)

80 लाख टन : हर साल
समुद्र में डंप किया जाता है
इसना प्लास्टिक कचरा

प्लास्टिक का इररेमाल धड़ल्ले से जारी
वह बात दीगर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके

गौठान से आजीविका प्राप्त हो सकती है, इस सपने को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना “नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी” ने पूरा कर दिया है। गांव में स्थापित परम्परागत गौठान को एक आदर्श गौठान के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। इसे आजीविका का स्रोत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बुड़ेनी में बनाया गया गौठान इस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। शासन का गौठान निर्माण का उद्देश्य ग्राम में लावारिस पशु जो इधर-उधर घूम-घूमकर किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, सड़कों पर दुर्घटना का कारण बनते हैं। जिससे स्वयं व मानव जाति के लिए खतरा पैदा होता है। इनकों बचाने एवं सुरक्षित रखने के लिए गौठान बनाया गया है।

गौठान में पशुधन विकास विभाग द्वारा सर्वप्रथम चारे की व्यवस्था हेतु लगभग 14 एकड़ चारागाह भूमि में 03 एकड़ में नेपियर घास लगाया गया, लगभग 01 एकड़ में एम.पी.चरी घास लगाया गया है, जिसे काटकर पशुओं को खिलाया जा रहा है। पैरा की व्यवस्था की गई है, अजोला टैंक का निर्माण, चापकटर, ट्रैक्सिस लगाकर पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण किया जा रहा है। गौठान में पशुओं से प्राप्त गोबर से जैविक खाद बनाने की व्यवस्था की गई है। इस जैविक खाद का उपयोग किसान अपने खेतों में कर सकेंगे।

बुड़ेनी के गौठान में लगभग 50 लावारिस पशु को भी रखा गया है। इन पशुओं के लिए शेड का निर्माण, चारा के लिए कोटना, पानी के लिए टांका एवं लगभग 03 एकड़ जगह में टहलने के लिए साफ-सुथरा जगह बनाया गया है। पशुओं की देखरेख करने के लिए चरवाहा कक्ष एवं चारागाह में सिंचाई व्यवस्था हेतु बोरपंप एवं तालाब का निर्माण भी किया गया है। कृषि विभाग द्वारा नाडेप का निर्माण, उद्यान विभाग द्वारा फलदार एवं छायादार पौधारोपण, छत्स्तड़ द्वारा बाड़ी में सब्जी बीज का रोपण जैसे कार्य जा रहा है। शासन के मंशानुरूप गौठान को आदर्श



ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बनेगा रोल माडल

[हेमलाल प्रभाकर]

आवश्यकता है। वहीं गौ पालन जो भारतीय संस्कृति एवं आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार रहा है, को संरक्षित और संवर्धन की भी आवश्यकता है। प्राचीन ग्रंथों, देवकाल और मानव सभ्यता के विकास में पशु पालन का विशेष महत्व देखने को मिलता है। गाय पालन समृद्धि का सूत्र है। आज की पीढ़ी गौ के महत्व को भूलती जा रही है। गौ पालन को पेचीदा और झांझट से भरा काम समझकर लोग इससे दूर होते जा रही हैं। दूध, दही, छाछ और दूध से बने मिष्ठान एवं अन्य व्यंजन की चाह तो सब रखते हैं, किन्तु गौ पालन कोई नहीं करना चाहता।



13



ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर से गौ पालन को बढ़ावा देने, इसके संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। छत्तीसगढ़ शासन ने गौ पालन के महत्व को बखूबी समझते हुए इस दिशा में योजना बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से गौठान निर्माण कर गौ संवर्धन की दिशा में काम शुरू किया गया है। गौ पालन होने से जहां लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध होगा, वहीं जैविक खाद के माध्यम से विषाक्त रासायनिक उर्वरकों से पैदा किए जा रहे फसलों पर रोक लगेगी। गौठान में पशुओं के सही देखभाल किए जाने, चारा-पानी मिलने से दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, यहां देशी नस्ल के संवर्धन का कार्य भी होगा। पशुओं के गोबर से बने कम्पोस्ट खाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और गोबर गैस लोगों को साफ सुधरा पर्यावरण हितेषी ईंधन भी उपलब्ध कराएगी। नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का अवसर मुहैया होगा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों की मूलभूत अधोसंरचना को विकसित कर देश व प्रदेश को समृद्ध बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की मूल पहचान यहां की सामाजिक समरसता, सरलता, आदिवासी संस्कृति, परम्परागत पशु आधारित कृषि से है। राज्य का समूचा ताना-बाना कृषि पर निर्भर करता है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है और यहां वर्षा आधारित छोटे-छोटे नदी नाले हैं। इन छोटे-छोटे

मॉडल बनने की ओर अग्रसर है।

[सहायक जनसंपर्क अधिकारी]

उत्तर बस्तर कांकेर = गौठान बना महिला स्व-सहायता समूह की आय का जरिया = तार-फेसिंग पोल बनाकर कमा रहीं अतिरिक्त आमदनी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना देना है बल्कि अपने पशुओं, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है। बाड़ियों के माध्यम से साग-सब्जी की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे एक फसलीय खेती से निजात तो मिलेगा ही किसानों की आर्थिक आमदनी में बढ़ोत्तरी होने तथा जैविक खाद से पोषक सब्जी एवं फलों का उत्पादन होने से स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में भी सुधार होगा। पुरखों द्वारा वर्षों से अजमायी गई इस विरासत को राज्य की मूल धरोहरों में फिर से शामिल करते हुए नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी को बचाने एवं बढ़ाने का अभिनव प्रयास दूरगामी साबित हो सकता है। छोटे-छोटे नालों एवं नदियों को बंधान कर न भूमि की नीचे के जल स्तर को बढ़ाना आज न केवल हमारी आवश्यकता है बल्कि मानव जीवन को बचाने की दृष्टि से विवशता भी बन चुकी है। आधुनिकता और विकास की दौड़ में मानव ने खुद के साथ खिलवाड़ कर अपने आप को असुरक्षित कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य फिर से अपनी सरलता, सहजता और कृषि आधारित पहचान बनाने तत्पर दिखायी देता है। महात्मा गांधी के 150 जयंती अवसर पर यह राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर बेहतर रोल



में बढ़े बदलाव आएंगे। आजादी के बाद भारतीय समाज ज्ञान-विज्ञान, समानता, चरित्र-निर्माण, सामाजिक सद्व्यवहार और सामाजिक सरोकार जैसे मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा लगातार खोता गया है। इसके विपरीत भ्रष्टाचार, धनलिप्सा, स्वार्थ, चालाकी और अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य हमारे समाज पर हावी होते चले गए। इस दौर में शिक्षकों की पेशागत प्रतिबद्धताओं और योग्यताओं में भी लगातार क्षरण होते देखा गया। आजादी के बाद के प्रारंभिक दशकों में शिक्षकों की कार्यदशाएं व वेतन-भत्ते अन्य पेशों की तुलना में कम थे। नतीजतन, पूरे देश में प्राथमिक, स्कूल और कॉलेज-यूनिवर्सिटी शिक्षकों के संगठनों ने शिक्षकों को लामबंद करके लगातार आंदोलन किए। शिक्षकों को राजनीतिक दलों, विधायिका में नामित किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने की छूट भी दी गई। शिक्षक संघों के आंदोलनों से जहां उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, वहीं दूसरी ओर, उन्हें शिक्षा के उन्नयन से लगातार विमुख होते हुए भी देखा गया। क्या स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से जुड़े राष्ट्रीय व प्रादेशिक संघ शिक्षा के प्रति शिक्षकों की उदासीनता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?

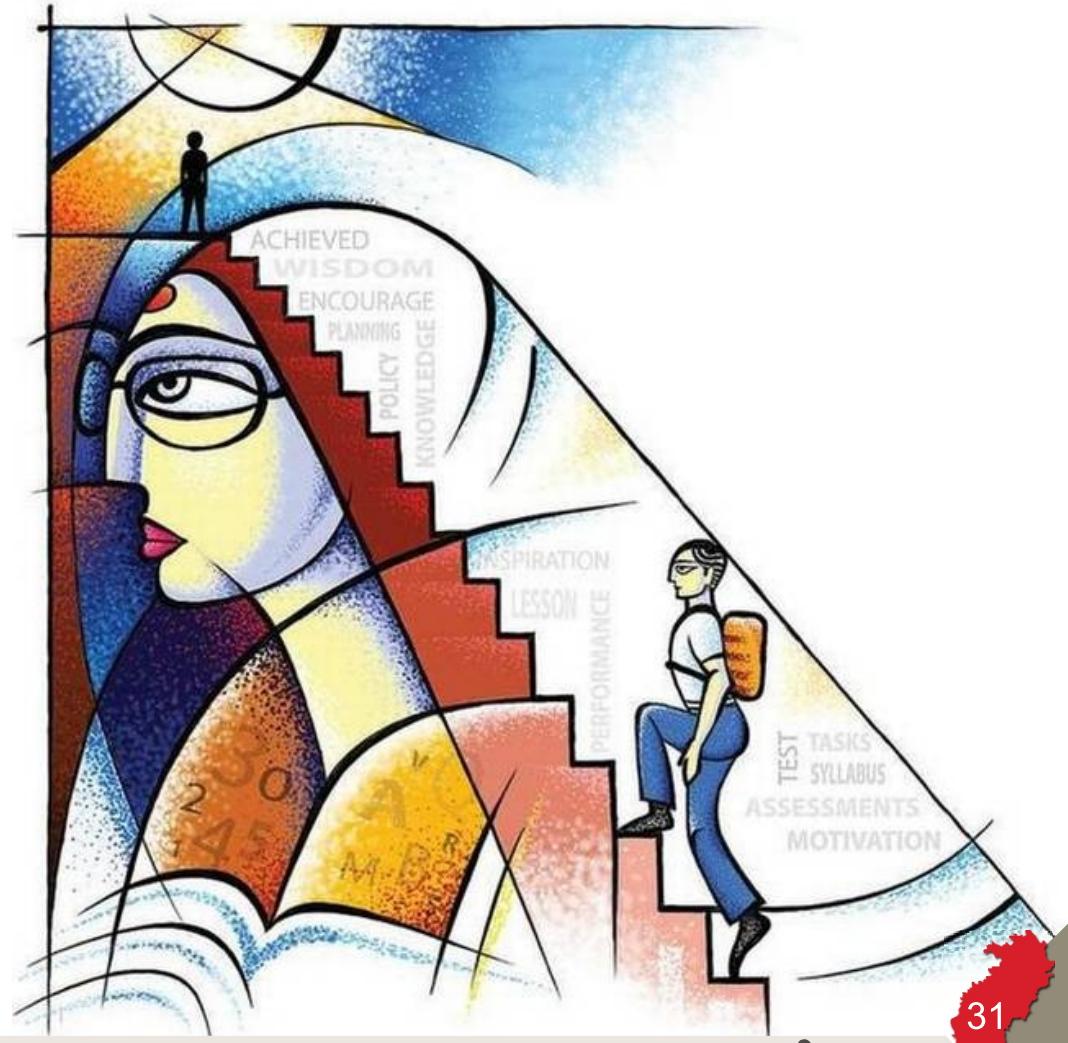
पिछले तीन दशकों में चौथे वेतन आयोग से लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों के वेतनमान में लगातार बढ़ोत्तरी होती गई। सन् 1977 में डिग्री कॉलेज के एक लेक्चरर को करीब हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था, जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लगभग 80,000 रुपये तक पहुंच गया है, यानी 42 वर्षों में 80 गुना। समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा में गिरावट का कारण उनके आर्थिक स्तर में सुधार के साथ-साथ उनकी पेशागत प्रतिबद्धता में कमी होना भी है। देश के कई राज्यों के जाने-माने

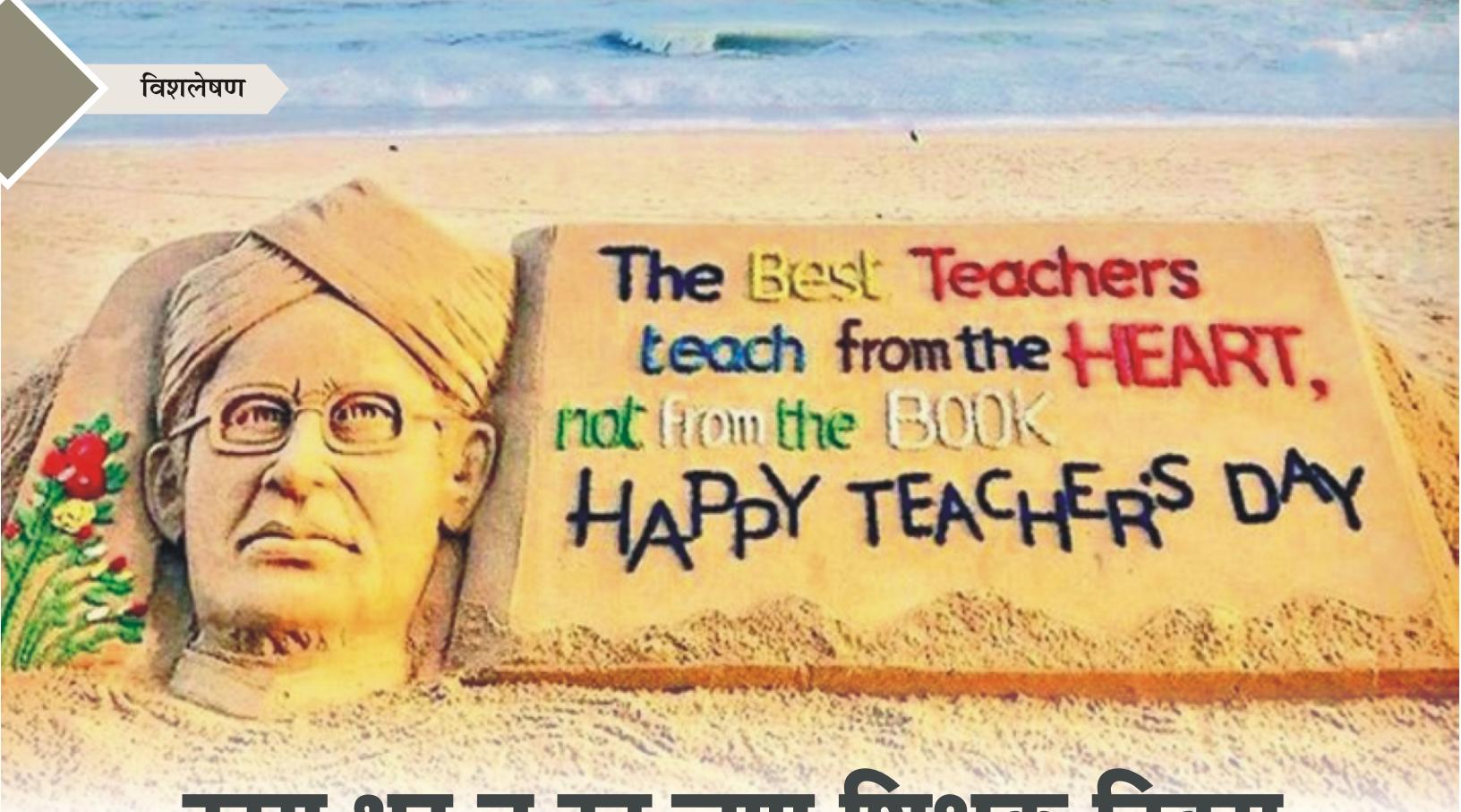
विश्वविद्यालयों में अकादमिक सत्र के दौरान कक्षाएं 100 दिन भी न लगना, इसका दुष्परिणाम ही कहा जाएगा। पिछले 73 वर्षों में कई बार शिक्षा और शिक्षकों के पेशे से संबंधित अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। सात बार शिक्षकों के वेतनमान को सुधारा गया, किंतु न तो शिक्षा में कोई व्यापक बदलाव आया और न ही शिक्षक के पेशे को समाज में कोई खास अहमियत मिल पाई। इसका एक मुख्य कारण यह रहा कि इन सभी बदलावों की दिशा ऊपर से नीचे की ओर थी और शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था की धुरी नहीं बनाया गया। यह मान लिया गया कि शिक्षक एक बड़ी प्रणाली का पुर्जा मात्र है, जो ठीक वही करता है, जैसे मशीन को चालू करने पर एक पुर्जे को करना होता है।

अभी भारत की स्कूली शिक्षा को लगभग

90 लाख सरकारी शिक्षक चलाते हैं, जो अपर्याप्त हैं। हमें कम से कम 20 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत होगी, तभी स्कूली शिक्षा सुचारू रूप से चलेगी। एक अहम सुझाव यह भी है कि तदर्थि शिक्षकों या पैरा शिक्षकों की प्रणाली को खत्म किया जाए, जिससे सभी शिक्षकों को एक जैसी सेवा-शर्त मिल सकें। स्कूली शिक्षा के अलावा हमारी उच्च शिक्षा में भी 12 लाख से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं, जो चार करोड़ युवाओं के भाग्य-निर्माता हैं। जाहिर है, आधुनिक भारत के भविष्य की तस्वीर इन 1.2 करोड़ शिक्षकों के हाथों से ही बनाई जाएगी। लेकिन यह तभी सुमिक्ष हो पाएगा, जब हम यह समझें कि शिक्षा में होने वाले किसी भी बड़े बदलाव को सफल बनाने में उनकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)





रस्म भर न रह जाए शिक्षक दिवस

[हरिवंश चतुर्वेदी]

देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाने का जो सिलसिला 1967 में शुरू हुआ, स्कूल-कॉलेजों में अब वह एक उत्सव का रूप ले चुका है। इस दिन जमकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और शिक्षकों की महिमा के गीत गाए जाते हैं। इस बीच हम यह भूल चुके हैं कि शिक्षक दिवस मनाने के सुझाव के पीछे क्या परिकल्पना रही होगी? सारे देश में मनाए जा रहे शिक्षक दिवस की धूमधाम के बीच आइए, जरा यह सोचें कि हमारे समाज में आज शिक्षा और शिक्षक के पेशे को कितना सम्मान दिया जाता है? क्या आज हम अपने किसी पुराने शिक्षक से मिलकर उतने ही भाव-विभोर होते हैं, जितने किसी नेता, अभिनेता, क्रिकेट स्टार, डांसर, गायक या साधु-संत से मिलने पर होते हैं? हमारी युवा पीढ़ी में कितने ऐसे होंगे, जो शिक्षक बनना चाहेंगे? क्या शिक्षक, लेखक और वैज्ञानिक जैसे पेशों के प्रति हम उदासीन नहीं हैं?

वैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं या कोई हॉलीवुड की एवेंजर जैसी फिल्म देख रहे हैं। सूचना क्रांति ने दुनिया को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, किंतु चौथी औद्योगिक क्रांति ऐसे बड़े बदलाव लाने जा रही है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। पर क्या हमारे राजनेता, नीति-निर्माता, शिक्षक और विद्यार्थी इस कदु सत्य से वाकिफ हैं कि आजकल उपलब्ध अधिकांश रोजगार वर्ष 2030 तक खत्म हो खटखटा रही है, किंतु हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली अभी भी 19वीं सदी में हुई दूसरी औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए रोजगार के ढांचे के अनुरूप कवायद कर रही है। आज विश्व स्तर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप 'शिक्षा 4.0' की बहुत चर्चा हो रही है, जिसे मोटे तौर पर चौथी शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। वर्ष 2030 तक पहुंचते-पहुंचते दुनिया में शिक्षक का पेशा खत्म नहीं होने जा रहा है, लेकिन यह तय है कि शिक्षक की महत्ता और भूमिका



पहुंचेगा। जैविक खाद के उपयोग से फसल की अच्छी पैदावार होगी। सरपंच ने बताया कि स्व-सहायता समूह के सदस्यों के साथ-साथ बेरोजगारों को भी चरवाहा का काम मिल गया है, वे चरवाहा पशुओं का देख-रेख करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वकांक्षी सुराजी योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके प्रारंभ होने से पशुओं के संरक्षण के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

पुरानी परम्परा को फिर कायम करने से खुश हैं ग्रामीण और चरवाहा

राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में गोठानों की पुरानी परम्परा फिर कायम होने से ग्रामीण और चरवाहा खुश हैं। बस्तर जिले के ग्राम पंचायत कोयनार के चालकीगुड़ा पारा में एक महीने पहले बने गोठान में ग्रामीण अपने मवेशियों को पानी पिलाने और इलाज के लिए लाने लगे हैं। इस गोठान के संचालन की जवाबदारी गांव की मोगराफूल महिला स्वसहायता को सौंपी गई है, जबकि पशुओं की



Latitude: 18.996909
Longitude: 81.921042
Elevation: 555.96m
Accuracy: 9.6m
Time: 08-29-2019 11:54
Note: kovnar noutuan darba

Powered by NoteCam



गया है, लेकिन चारे को बढ़ने में अभी वक्त लगेगा। चालकीगुड़ा के किसान श्री संपत्त बघेल ने बताया कि गोठान बनने से गांव वालों को सुविधा हुई है। यहां मवेशियों के लिए पानी और उपचार दोनों की सुविधा है। उन्होंने बताया कि अभी तो चारों तरफ पर्याप्त चारा है, लेकिन गर्मियों में गोठान में पानी और चारे का फायदा मवेशियों को मिलेगा। इसी गांव के पनारागुड़ा पारा के किसान श्री गणपत मौर्य ने बताया कि गोठान और पनारागुड़ा के बीच नाले पर पुल पूरा नहीं बनने के कारण वे मवेशियों को गोठान में नहीं ला पा रहे हैं। पुल के बनने बाद उनके गांव के लोग भी गोठान में मवेशियों को लाएंगे।

चरवाहा श्री देबो कश्यप ने बताया कि सरकार द्वारा गोठानों के लिए हर माह दस हजार रुपए दिए जाने की जानकारी मिली है। यह राशि मिलने से गोठानों का बेहतर संचालन हो सकेगा। गोठान में मोगराफूल महिला स्वसहायता समूह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाया जा रहा है। इसके लिए गोठान में

जिसमें गोबर एकत्र करने का काम एवं रख-रखाव यहां के जय गणेश महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। यहां प्रति सप्ताह गौठान समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न मुददों पर चर्चा कर विकास के लिए कार्य योजना बनाते हैं। गोठान निर्माण के कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का विशेष योगदान है। गौठान में ग्राम के समस्त पशुओं को एकत्र कर पशुधन विकास विभाग द्वारा टीकाकरण, उपचार, दवा वितरण कृमिनाशक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। गौठान में पानी की समुचित व्यवस्था के लिए दो तालाब, एक डबरी एवं बोर का खनन किया गया। यहां कोटना एवं पानी टंकी निर्माण कर पशुओं को पानी पिलाया जाता है तथा नियमित रूप से इसका साफ-सफाई भी किया जाता है। इसके अलावा गौठान से लगा हुआ 3 एकत्र भूमि पर चारागाह की व्यवस्था की गई, जिसमें नेपियर घास, मक्का के साथ ही साथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है। यहां घुरुवा गौठान एवं चारागाह में लक्ष्मी महिला स्व



सड़क पर सारे ऐक्सिडेंट एक ही वजह से नहीं होते

[गुलशन राय खत्री]

संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद अब देश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को लेकर बहस हो रही है। जुर्माने की राशि में दस फीसदी से दस गुना तक की बढ़ोतरी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि एक झटके में इतना जुर्माना बढ़ाना उचित नहीं है लेकिन सरकार का तर्क है कि बेकाबू होती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसी जाए। इसी वजह से जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है ताकि वाहन चलाते हुए लोग नियम न तोड़ें और भारी जुर्माने की वजह से उनमें डर भी हो।

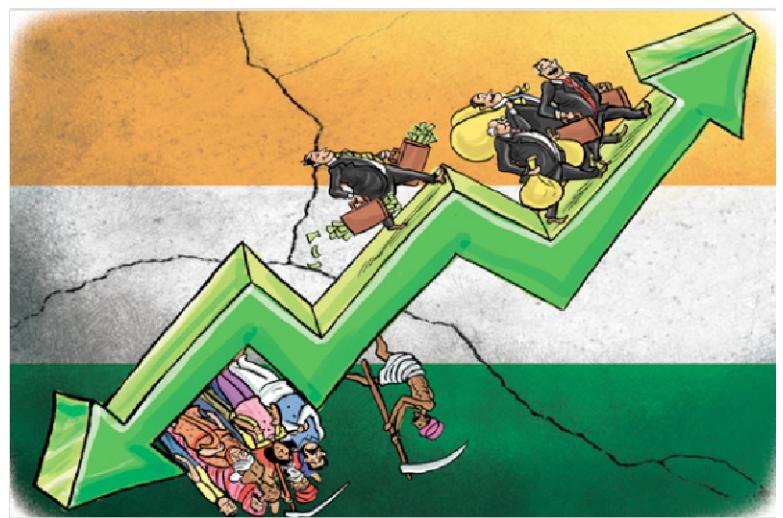
सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश की स्थिति सचमुच गंभीर है। सालाना करीब डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। साल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक उस साल 4 लाख 64 हजार 910 ऐक्सिडेंट हुए जिनमें एक लाख 47 हजार 913 लोगों की जान गई और चार लाख 70 हजार से अधिक लोग घायल हो गए। इसका अर्थ है कि देश में हर घंटे 53 ऐक्सिडेंट होते हैं और इनमें 17 लोगों की जान चली जाती है। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में 48 हजार 746 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई जो ट्रॉफीलर पर थे। इनमें से 73 फीसदी से अधिक ने हेलमेट नहीं पहना था। 76 फीसदी ऐसे ऐक्सिडेंट थे, जिनमें या तो वाहन ओवर स्पीडिंग पर था या फिर गलत

अब तक ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले इस तरह की एक्सपर्ट टीमें बनाने की कावायद करे जो हर एंगल से जांच कर ऐक्सिडेंट की सही वजह पता कर सके। सही कारण सामने आने पर ही उसका निवारण किया जा सकेगा। सिर्फ अनुमान के आधार पर उपाय करना कितना फायदेमंद होगा, कहा नहीं जा सकता।

बहरहाल, भारत में ऐक्सिडेंट की एक बड़ी वजह तो यही है कि यहां ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था बेहद लचर है। कमर्शल वीइकल के लिए तो हाल के सालों में कुछ ट्रेनिंग सेंटर खुले भी हैं लेकिन प्राइवेट वीइकल चलाने के लिए अक्सर लोग आसपास के मोहल्लों में खुले ट्रेनिंग सेंटरों की मदद लेते हैं।

ये ट्रेनिंग सेंटर कितने कारगर हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जब ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों के टीचरों का एग्जाम लिया गया तो ‘गुरु’ ही फिसड़ी निकले। देश में प्रशिक्षित ड्राइवरों की भी अत्यधिक कमी है। इनकी मौजूदा संख्या जरूरत से 20 लाख कम बताई जाती है। इस कमी का भी कारण ट्रेनिंग का अभाव ही है। सरकार वार्कइंसेंट दुर्घटनाओं को रोकना चाहती है तो उसे इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा।

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने



मुश्किलों का अंबार है, रुपया परवरदिगार है

[अवधेश व्यास]

बावा, फिर घूम गएला है भेजा, तबियत हो गएली है बेमजा। अबी दिल बोल रएला है, बोले तो कटोरा ले के घूमने वाले पाकिस्तान कू बी भूल जा। भूल जा, बोले तो भूल जा, के कश्मीर में है खामोशी का पेहरा, बोले तो खो गएला है जन्त्र का मजा। अबी मंदिर जबी बनेंगा, तबी बनेंगा, अबी सिरिप घंटा बजा। हूस्टन कू अबी क्या देखेंगा सजा धजा, कायकू बोले तो टीवी पे एनआरजी की एनर्जी देखने वालों का हिल गएला है एक एक पुरजा। देखे नई क्या भाय, बोले तो चिरकुट कांदे के बी बड़ गएले हैं भाव, बोले तो बड़ गएला है दरजा।

बावा, अपुन के इदर तो ये पएला से ईच हैं, बोले तो जो गाय ढोर कू जाते हैं चराने, उनके कोई नई सुनता फसाने, पन जो डॉगी कू सुबे शाम ले जाते हैं धुमाने, उनकू दर रोज मिलते हैं दौलत कमाने के बहाने। पन अबी तो शेर की खाल में गीदड़ लगे हैं गुरने। टाइम तो ये बी आ गएला है बावा, बोले तो सोने का भाव पड़ रएला है फीका, बोले तो अबी सोने की शक्त बी लगी है मुरझाने और चोर लोक बी अबी लगे हैं कांदे चुराने।

अबी क्या बोलेंगा भाय, अबी गरीब कू कांदे खाने के बी हैं वांदे। बजार में दुकनदार से पूछेंगा, 'कैसे दिए कांदे', तो वो अपुन के झोले कू देख के बोल देता है, 'चल हवा आन दे'। अपुन थोड़ा भोत तो ले ईच सकता है, पन फिर अपुन बी बोल देता है, बोले तो, 'चल

जान दे'। कबी मिनिस्टर बोलता था, अपुन के खजीने में फौरेन करेंसी का भरचक स्टॉक है और अबी टीवी पे मिनिस्टर बोल रएला था, बोले तो अपुन के पास कांदे का स्टॉक फुलटू फटाक है।

अपुन के यार सलीम पानी का क्या है ना भाय, बोले तो फोर्स में होएंगा तो उड़ जाता है, ढलान पे होएंगा तो गिर जाता है और अपुन के जैसा खजूर की बात पे फिर जाता है-'बस क्या भिड़, कांदे कू छील के बी नई समजा वांदे कू। अबे ठंडी बिस्मिलाह, तेरे कू समजने कू नई होएंगा, बोले तो किदर कांदे ने किया है। अबी कांदा सिरिप कांदा नई, जिंदगी में घुस गएला चक्र है, बोले तो कल्चर है।'

अपुन बोला, 'बावा, कांदा आंख में है धुसता, तो है रुलाता, तुम ये जिंदगी का क्या चक्र है बताता।'

पानी एकदम गरम तवे पे छन से गिरा, 'कुच आता न जाता, नाम सुजाता, बात बात पे खोपड़ी खुजाता। भिड़, अबी अपुन के इदर कांदे का माफिक लोक हैं, एक छिलका उतरता है, एक नवा चेहरा उभरता है, नवी बात उगलता है, पएला की बात से मुकरता है। सामने मीठा मीठा बोलता है, बोले तो रस टपकता है और पीठ का पीछा लोचा पकता है। अबी देखा था ना वो बीड़ियो, बोले तो कोई टीवी एंकर माइक बंद करना भूल जाती है और कोई लीडर का वास्ते ऐसी बात बोल जाती है जो उस एंकर के अपने हैं।

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

बाड़ी योजना से सज्जी बेचकर मनीराम हुए खुशहाल

रायपुर, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना- नरवा, गरुवा, घुरुवा अड बाड़ी अंतर्गत बाड़ी लगाने से बढ़ी आमदनी से बेमेतरा जिले के श्री मनीराम के जीवन में खुशहाली आ गई है। बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम दमईडीह निवासी किसान श्री मनीराम चन्द्राकर ने बताया कि वे लगभग 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र में सज्जी की खेती करते हैं।

पहले वह मुंगफली, मक्का, चेंचभाजी व चौलाई लगाते थे। लेकिन सरकार की नरवा, गरुवा, घुरुवा अड बाड़ी योजना आने के बाद उद्यानिकी विभाग की तकनीकी सलाह से पुरानी बाड़ी का पुनरोद्धार किया। इसके लिए बीज, खाद, रासायनिक दवा एवं वर्मी बेड के द्वारा बाड़ी को सुव्यवस्थित कर उन्नत किस्म की सज्जी भिण्डी, लौकी, तरोई, मिर्च,



कि विगत 20 दिनों से कर दो दिन के अंतराल में सज्जी बेचकर अब तक 13 हजार 080 रुपय कमाई कर चुके हैं।

कृषक द्वारा सरकार द्वारा संचालित नरवा, गरुवा, घुरुवा अड बाड़ी की तारीफ करते हुए आभार व्यक्त किया है।

बाड़ी की भिण्डी ने नरसिंग के जीवन में भरे नये रंग



के बाद शासकीय उद्यान रोपणी मोहगांव के अधिकारियों ने मेरे घर आकर योजना की जानकारी दी और भिण्डी का एक किलो बीज दिया। उन्होंने इसके साथ दवाई, खाद व वर्मी टांका भी दिया। बीज लगाई पर पहली बार में ही 20-25 किलो भिण्डी फसल की उपज हुई। अब 7-8 बार की तुड़ाई में साथ 50-70 किलो भिण्डी की उपज निकल रही है।

श्री नरसिंग ने खुश होकर कहा कि चिलहर बाजार में भिण्डी का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की बाड़ी योजना हम जैसे छोटे हित्राहियों के लिए एक लाभकारी योजना है। इससे हमारा दैनिक गुजारा भी चल रहा है। उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति हृदय से आभार प्रगट किया है।

राज्य सरकार की नरवा, गरुवा, घुरुवा अड बाड़ी योजना से लोगों को मुनाफा मिलने लगा है। बेमेतरा जिले के साजा विकासखण्ड के ग्राम खपरी के लघु कृषक नरसिंग वर्मा ने



कश्मीर में नई सुबह का आगाज खत्म हुआ एक इतिहास

[प्रभुनाथ शुक्ल]

जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसले अपने आप में ऐतिहासिक है। पूरे देश में जशन का महौल है। लेकिन इस फैसले से वोटबैंक की राजनीति करने वालों को गहरा आघात पहुंचा है। कश्मीर पर सारी अटकलें और संशय खत्म हो गए हैं। मोदी सरकार के मिशन कश्मीर की सारी तस्वीर साफ हो गई है। जिसकी आशंका जतायी जा रही थी वहीं हुआ। सरकार ने राज्य से धारा-370 के लिए कदम बढ़ा दिया। गृहमंत्री अमितशाह ने संसद में इसे हटाने की सिफारिश भी पेश कर दी। जम्मू-कश्मीर को विशेष नागरिक सुविधा देने वाली धारा-35 ए को खत्म कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर राज्य अब एक और हिस्से बन्ते जाएगा, दूसरा राज्य लद्दाख होगा। निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा फैसला आया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा और सुविधाएं देने वाली धारा 35 को खत्म कर उसे भारतीय गणराज्य के सामान नागरिक अधिकारों से जोड़ दिया गया है। अब आप वहाँ जमीन भी खरीद सकते और शादियां भी कर सकते हैं।

क्योंकि 35 ए का आदेश राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया था। लिहाजा उसे उहाँ तरीके से खत्म कर दिया गया है। मोदी सरकार के निर्णय से कांग्रेस और पूरा विपक्ष सकते में है। लेकिन पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। क्योंकि कश्मीर एक देश एक कानूनी की तरफ बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमितशाह ने राज्यसभा में इस संवैधानिक संशोधन को पेश कर करके कश्मीरी नेताओं

करने में सक्षम हैं।

कश्मीर में किसी भी हालात से निपटने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है। पूरे जम्मू-कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा और सतर्कता को लेकर सारे आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मीडिया और प्रबुद्ध वर्ग पहले ही यह आशंका जता रहा था कि सरकार कश्मीर पर साहसिक निर्णय ले सकती है।

भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने धारा-370 के तहत कश्मीर के नागरिकों को विशेष सुविधा के लिए 14 मई 1954 को धारा 35 एक का विशेष आदेश जारी किया था। 1956 में जम्मू-कश्मीर के संविधान में वहाँ की नागरिकता को परिभाषित किया गया। जिसके अनुसार 1954 के पूर्व या यह कानून लागू होने के 10 साल पहले से जो लोग कश्मीर में निवास कर रहे हैं यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। राज्य को मिले इस विशेष दर्जे के अनुसार देश के दूसरे राज्य का वहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था और न ही वहाँ की नागरिकता हासिल कर सकता था। शरणार्थियों को वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। बोट देने का अधिकार नहीं था। स्कूलों में उनके बच्चों का दाखिला तक नहीं हो सकता था। वहाँ की लड़की ने अगर किसी बाहरी व्यक्ति से शादी कर ली तो उसे वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती थी। हालांकि यह कानून संसद के जरिए नहीं पारित था। यह केवल राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया विशेष अधिकार था। जिसे मोदी सरकार ने साहत दिखाते हुए राष्ट्रपति के जरिए ही खत्म कर

उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही सुमित्रा नंदन पंत से प्रेरित होकर लिखना शुरू कर दिया था और अपना उपनाम 'परदेसी' रखा था।

उपनाम था परदेसी

1949 में जब उनका विवाह हुआ, तो कार्ड पर दुष्यंत कुमार त्यागी 'परदेसी' छपवाया गया था। हां, इलाहाबाद पहुंचकर उहाँ साहित्य का वातावरण मिला। वे कहानियां और गीत लिख रहे थे। हरिवंश राय बच्चन उनके गुरु और मार्गदर्शक बने, वहीं कमलेश्वर और मार्कडेय की मित्रता ने इस यात्रा को नया आयाम दिया।

कमलेश्वर-दुष्यंत-मार्कडेय की तिकड़ी

कमलेश्वर-दुष्यंत-मार्कडेय की तिकड़ी को साहित्य जगत में 'त्रिशूल' के नाम से पुकारा जाने लगा। तीनों ने मिलकर 'विहान' पत्रिका भी निकाली। आकाशवाणी की नौकरी के कारण वे दिल्ली और फिर उसके बाद भोपाल में रहे। उस समय भोपाल में उर्दू के तरकीपसंद शायर ताज भोपाली और कैफ भोपाली सक्रिय थे। संभवतः यहाँ उहाँ एहसास हुआ होगा कि गजल को जनता के पक्ष में हथियार बनाया जा सकता है।

शोषण के विरुद्ध बिगुल

दुष्यंत की गजलों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे आम लोगों की जुबान होकर जुल्मों सितम और शोषण के विरुद्ध बिगुल बन गईं। उनके आखिरी और एकमात्र गजल संग्रह 'साये में धूप' ने हिंदी साहित्य को गजल का न सिर्फ उपहार दिया, बल्कि लोकप्रियता का वह कीर्तिमान स्थापित किया कि उनकी गजलें और शेर सभी की जुबान पर आज भी चढ़े हुए हैं।

संग्रहालय में सहेजी गई कई चीजें

भोपाल में इस महान कवि की यादों को सहेजा गया है दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में। उसके निदेशक राजुरकर राज कहते हैं, '1995 में स्थापित इस संग्रहालय में दुष्यंत कुमार की पांडुलिपियां, घड़ी, लाइसेंस, बंदूक, हुक्का, पासबुक आदि को सहेजा गया है। वे बताते हैं, उनकी वे पांडुलिपियां भी हैं, जिनमें उन्होंने एक ही शेर

को कई बार अलग-अलग तरह से लिखा है।'

ऐसी थी सोच

अवश्य ही यह दुष्यंत की यह सोच थी कि शेर को इस तरह कहा जाए कि वह सीधा ब्रह्मस्त्र की तरह असर करे। आम इंसान के प्रति दर्द और विसंगतियों के प्रति रोष दुष्यंत कुमार में शुरू से दिखता है। मजदूर और शोषित वर्ग के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए जिस अस्त्र की जरूरत थी, वह उहाँ अंत में गजल के रूप में मिला, इसके पहले का उनका साहित्य भी युद्धरत कवि का आख्यान ही है।

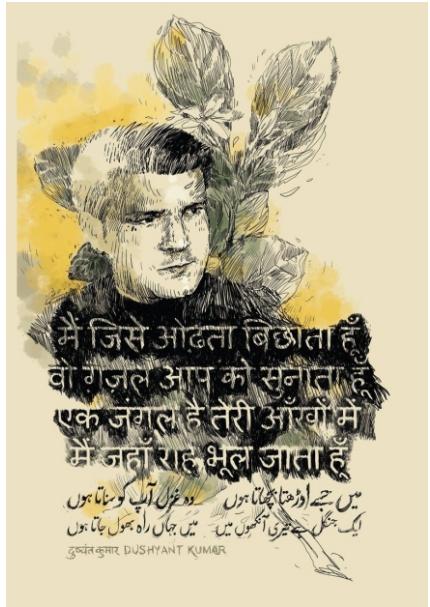
सूर्य का स्वागत पहला कविता संग्रह

उनका पहला कविता संग्रह 'सूर्य का स्वागत' 1957 में आया था, जिसमें अधिकांश

छंदमुक्त कविताएं थीं, जिसमें विसंगतियों को नए मुहावरों के साथ उकेरा गया था। यहाँ तक कि काव्य नाटक 'एक कंठ विषपायी' में भी वह सती-शिव की कथा के जारी रही अपने समय की कथा कहते हैं। वहीं 'आवाजों के घेरे में' विद्रोही कवि के रूप में उभरते हैं। अपने उपन्यास 'अंगन में एक वृक्ष' में भी उन्होंने सामंतवाद और मजदूरों के शोषण को विषय बनाया। जब कमलेश्वर ने 'कितने पाकिस्तान' लिखना शुरू किया था, उस समय मुझे दिल्ली के इरोज गार्डन कॉलोनी स्थित उनके घर जाने का अवसर मिला था।

खुशमिजाज, उत्साही, जिंदादिल इसान थे

दुष्यंत दुष्यंत की चर्चा आने पर उन्होंने बताया था कि दुष्यंत खुशमिजाज, उत्साही, जिंदादिल,



दुष्यंत कुमार की बराबरी आज तक नहीं कर पाया कोई कवि

[विवेक भट्टनागर]

दुष्यंत कुमार एक मशाल की तरह चमके। उनके भीतर असहमति की जो चिंगारी थी उसे वह हर हृदय के भीतर दहका कर शोषित व सर्वहारा वर्ग के शिव की रूपरेखा रचना चाहते थे।

समय सदैव उन्हें ही याद रखता है, जो उसके साथ चलते हुए सजगता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ न सिर्फ काम करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की राह भी प्रशस्त करते हैं। और फिर समय गवाह है कि साहित्य उन्हें ही अपने हृदय में रखता है, जो निर्भीकता से अपनी काव्यधर्मिता का निर्वाह करते हैं। हिंदी साहित्य में दुष्यंत कुमार (1933-1975) और उनकी गजलों को जो लोकप्रियता मिली है, वह आज तक किसी अन्य कवि को नहीं मिली। दुष्यंत कुमार आखिरी दौर में जिस कालखण्ड को जी रहे थे, वह राजनीतिक रूप से उथल-पुथल वाला दौर था।

उपेक्षित और प्रताड़ित था आम इंसान
निरंकुश सत्ता की नीतियों के कारण आम इंसान उपेक्षित और प्रताड़ित था। वहीं हिंदी कविता की दो धाराएं समानांतर रूप से चल रही थीं। एक नई कविता की, जो छंदमुक्त और किलष्ट वैचारिकता की थी। संभव है कि वैचारिक दुर्बोधता उन कवियों की कोई चालाकी रही हो, ताकि वे सत्ता की नजरों में चढ़ने से बचे रह जाएं। लेकिन उनकी जनपक्षधरता निष्फल हो रही थी, क्योंकि

जिस मजदूर, वंचित, शोषित वर्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, वह भी किलष्ट

वैचारिकता के कारण उनसे जुड़ नहीं पा रहा था।

युग की मांग थी क्रांति जबकि उस युग की मांग क्रांति की थी। वह छुपकर वार करने का नहीं, युद्धरत होने का समय था। कविता की दूसरी धारा गीतों की थी। हरिवंश राय बच्चन और नीरज जैसे कवि पत्रिकाओं और मंचों पर समादृत थे। कुल मिलाकर, दमनकारी सत्ता को आईना दिखाने और जनता को मरहम लगाने का प्रयोजन नहीं बन पा रहा था। उलटे, ऐसे कवियों की भी एक भीड़ पैदा हो गई थी, जो निहित स्वार्थों के कारण सत्ता के प्रशस्ति गायन में रत थे।

मशाल की तरह चमके दुष्यंत

ऐसे समय में दुष्यंत कुमार एक मशाल की तरह चमके। उनके भीतर असहमति की जो चिंगारी थी, उसे वह हर हृदय के भीतर दहका कर शोषित व सर्वहारा वर्ग के शिव की रूपरेखा रचना चाहते थे। उन्होंने कविताओं-गीतों से शुरूआत की, उपन्यास लिखे,

कहानियां लिखीं, सभी में उनकी जनपक्षधरता और कवि-धर्म की छटपटाहट नजर आई। लेकिन उन्हें तलाश थी ऐसी काव्य-विधा की, जो जनआंदोलन का रूप ले सके। उन्हें गजल के रूप में यह हथियार मिला। इस हथियार को उन्होंने स्वयं गढ़ा और उसमें सान रखी। हालांकि कविताएं लिखना

दिया। निश्चित तौर पर अपने आप में यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित कर भाजपा ने कश्मीर और पाकिस्तान राग अलापने वाले नेताओं को जर्मान दिखा दिया है। लद्दाख को अलग राज्य बनाकर वहाँ सीटों को नए जरिए से परिसीमित कर लोकतंत्र की नई जमीन तैयार की जाएगी। देश के सुरक्षा के लिहाज से भी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। कोई भी व्यक्ति सरकार के फैसले के विरोध में नहीं खड़ा है। सिर्फ चुनावी और वोट बैंक की राजनीति करने वाले आंसू बहा रहे हैं। सरकार की इस नीति से कश्मीर अब पूरे नियंत्रण में होगा। अलगाववादी अपने आप बिल में घुस जाएंगे। आतंकवाद का सफाया होगा। क्योंकि नये गठन के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा। राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। कश्मीर देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम राज्य है। पाकिस्तान और चीन की कुटिल नीति की वजह से देश की सामरिक सुरक्षा के लिए वहाँ स्थितियां अनुकूल नहीं थी। लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद स्थितियां बदलेंगी और इस फैसले से जम्मू-कश्मीर का सारा नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होगा। सरकार ने इस फैसले से अमेरिकी को भी जमीन दिखाई है। जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप कश्मीर मसले पर मध्यस्थता का राग अलाप रहे थे। भारत सरकार का यह फैसला दुनिया को एक नया संदेश देने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के लिए भी कड़ा संदेश है।

मोटी सरकार ने कश्मीर के राजनैतिक दलों, अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान से निपटने के लिए सारी तैयारी कर ली है। जम्मू-कश्मीर में भारी तादात में फोर्स तैनात कर दी गयी है। नागरिक सुरक्षा को देखते हुए सारी हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी थीं। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह दिन बेहद खास है। इतिहास की भूल को सुधारते हुए राग ट्रिहित में यह कदम स्वागत योग्य है। इस मसले पर सरकार की जितनी तारीफ की जाय वह कम है। कश्मीर से 370 हटने का भी रास्ता साफ हो गया है। देश में अब एक साफ-सुधारी राजनीति का दौर शुरू हुआ है। अब लोकतंत्र को सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का जरिया समझना बड़ी भूल होगी। देश की जनता जो चाहती है उसे सरकारों को हर हाल में पूरा करना होगा। अब वह दौर आ गया है जब अलगाववादियों को वर्देमातरम् और जयहिंद बोलना होगा। जम्मू-कश्मीर में अब सिर्फ भारतीय तिरंगा लहराएगा। जम्मू-कश्मीर को एक नई आजादी मिली है। इसका स्वागत करना चाहिए। सरकार को अलगाववादियों को सबक सीखाना चाहिए। लेकिन नागरिक अधिकारों का दमन न हो इसका विशेष ख्याल रखना होगा।

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं

संयत रहना होगा

सरकार का कहना है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अनुच्छेद 370 के रहते राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। इसकी मौजूदगी केंद्र सरकार के हाथ बांध देती थी और वह राज्य की बेहतरी के लिए अहम फैसले नहीं कर पाती थी।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में ऐतिहासिक फैसला करते हुए अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटा दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 का खंड-ए बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सरकार ने सोमवार को राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश किया जिसे बाद में पास कराया जाएगा। जम्मू-कश्मीर की स्थिति दिल्ली और पुदुच्चेरि जैसे केंद्र शासित प्रदेश वाली होगी, यानी यहाँ विधानसभा रहेगी। जबकि लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ जैसी होगी, जहाँ विधानसभा नहीं होगी। सरकार का कहना है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अनुच्छेद 370 के रहते राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। इसकी मौजूदगी केंद्र सरकार के हाथ बांध देती थी और वह राज्य की बेहतरी के लिए अहम फैसले नहीं कर पाती थी।

अनुच्छेद 370 शुरू से ही राष्ट्रीय बहस का मुद्दा रहा है। देश का एक तबका इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत से जोड़ने वाली कड़ी मानता रहा है। लिहाजा उसकी मान्यता रही है कि इसमें कोई बुनियादी छेड़गाड़ कश्मीरी जनता की भावनाओं के अलावा भारत की मूल संवैधानिक प्रस्थापनाओं के भी खिलाफ जाएगी। जबकि दूसरी राय यह रही है कि इसके तहत मिलने वाले अधिकार और व्यवस्थाएं भारत की एकात्मकता के खिलाफ हैं और इनमें ज्यादातर दशकों पहले बेअसर हो चुकी हैं। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अपने पुराने जनसंघ वाले दौर से ही इसे हटाए जाने के पक्ष में रही है और यह बात उसके घोषणापत्र में भी शामिल रही है। जाहिर है, बीजेपी सरकार के सामने राज्य के विकास को लेकर अपनी परिकल्पनाएं होंगी। उम्मीद की जाती है कि उसने काफी सोच-विचार के बाद ही यह कदम उठाया है। वहाँ किसी भी जोखिम से निपटने का हौसला उसके पास होगा और इसके लिए जरूरी तैयारी भी उसने कर रखी होगी लेकिन यह धारणा बनाना उचित नहीं है कि धारा 370 खत्म होने से कश्मीर की समस्या रातोंरात सुलझ जाएगी। इस कदम को लेकर कुछ गहरे और न्यायसंगत सवाल हैं, जिन्हें राष्ट्रवाद के हल्के में किनारे नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 370 को कश्मीरी अस्मिता का प्रश्न मानने वाले स्थानीय राजनेता इस फैसले के प्रति अपना विरोध जता चुके हैं और उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती मिलना स्वाभाविक है। अलगाववादी ताकें इसे मुद्दा बनाकर अपने भारत विरोधी अभियान को चरम पर ले जाने का प्रयास कर सकती हैं। उनसे निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को मुस्तैद रहना होगा। इसे किसी जीत या हार के रूप में प्रचारित करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे बाकी देश में भी तनाव पैदा हो सकता है। यह वक्त कश्मीरियों से सघन संवाद में जाने का है। दरअसल कश्मीर को इस कदम से आगे एक हीलिंग टच की जरूरत है।

कश्मीर पर बुद्धिजीवियों की तकलीफ !

कश्मीर पर आए फैसले के बाद कुछ लोगों को तकलीफ है कि इस पर इतने जोक क्यों बनाए जा रहे हैं? इनका मानना है कि ऐसा करने से हम आम कश्मीरी की भावनाएं आहत कर रहे हैं। वहाँ कुछ लोग इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर की जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया।

दरअसल दिक्कत ये है कि जब भी इंसान खुद को बुद्धिजीवी मान लेता है तो उसे मुख्यधारा से जुड़ी हर चीज से नफरत हो जाती है। अगर राष्ट्रप्रेम मुख्यधारा है, तो बुद्धिजीवी राष्ट्रहित से जुड़ी हर बात के खिलाफ जाकर अपना अहम तुष्ट करता है। लोग क्रिकेट की जीत पर खुश होते हैं। बुद्धिजीवी कहता है कि क्रिकेट कोई खेल ही नहीं है। बुद्धिजीवी को राष्ट्रप्रेम बहुत मेनस्ट्रीम लगता है। इसलिए वो खेलों की जीत पर लोगों की खुशी को उग्र राष्ट्रवाद बताता है। वो गौमूर पर जोक बनाता है। पुलवामा में भारतीय सैनिकों की शहदत पर कश्मीरियों के How is the Jaish जैसे जोक्स शेयर करता है मगर उसे कश्मीर में प्लॉट खरीदने वाले जोक उसे Insensitive लगते हैं! उसे एक खास नेता से नफरत होती है और जब-जब उस विचारधारा से जुड़े

लोग क्रिकेट से लेकर कश्मीर तक किसी भी चीज का जश्न मनाते हैं तो बुद्धिजीवी के मन में वो खीझ होती है।

यही वो बुद्धिजीवी है जो गली में गुबारे के लिए हुए बच्चों के झगड़े में भी प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर की जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया।

दरअसल दिक्कत ये है कि जब भी इंसान खुद को बुद्धिजीवी मान लेता है तो उसे मुख्यधारा से जुड़ी हर चीज से नफरत हो जाती है। अगर राष्ट्रप्रेम मुख्यधारा है, तो बुद्धिजीवी राष्ट्रहित से जुड़ी हर बात के खिलाफ जाकर अपना अहम तुष्ट करता है। लोग क्रिकेट की जीत पर खुश होते हैं। बुद्धिजीवी कहता है कि क्रिकेट कोई खेल ही नहीं है। बुद्धिजीवी को राष्ट्रप्रेम बहुत मेनस्ट्रीम लगता है। इसलिए वो खेलों की जीत पर लोगों की खुशी को उग्र राष्ट्रवाद बताता है। वो गौमूर पर जोक बनाता है। पुलवामा में भारतीय सैनिकों की शहदत पर कश्मीरियों के How is the Jaish जैसे जोक्स शेयर करता है मगर उसे कश्मीर में प्लॉट खरीदने वाले जोक उसे Insensitive लगते हैं! उसे एक खास नेता से नफरत होती है और जब-जब उस विचारधारा से जुड़े

उठेगी, तब क्या करेंगे? क्या ऐसे लोग भी अगर बहुसंख्यक हो गए, तो क्या तब भी जनता की भावनाओं को सम्मान करने को कहेंगे?

क्या तब भी plebiscite की वकालत करेंगे? क्या आप नहीं जानते जिन कथित हिंदू कट्टरपंथियों को आप देश के कथिथ सेक्युलर ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, कश्मीरियों की भावनाओं का सम्मान करने के बाद आपके उसी कथित हिंदू कट्टरपंथ को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

आप 370 हटाने पर खतरनाक अंजाम की चेतावनी देते हैं। खून-खराबे की आशंका जाहिर करते हैं। मैं पृष्ठता हूं जिस कश्मीर में पिछले 30 सालों में 40 हजार लोग अपनी जवान गंवा चुके हैं, वहाँ इससे बुरा और क्या हो सकता है? जिस राज्य से 5 लाख कश्मीरी अपने हिंदू होने के कारण निकाले जा चुके हैं उससे ज्यादा खतरनाक अंजाम और क्या होगा?

धरती सूरज के चारों तरफ धूमती है तो दिन रात बनते हैं। मगर आप किसी समस्या के चारों तरफ 70 साल तक धूमते रहें, तो वहाँ सिर्फ रात बनती है। अंधेरा छाता है। जैसा अंधेरा कश्मीर में 70 सालों से छाया हुआ था और आज अगर धुरी बदली है, तो इंतज़ार कीजिए वहाँ उजाला भी होगा।

और आज उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पाकिस्तान में जाने दिया जाए, तो कल को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है और जब-जब उस विचारधारा से जुड़े

कहा कि पाकिस्तान के साथ कई मौकों पर बातचीत शुरू हुई लेकिन ये रुक गयी तो उसकी बजह पाकिस्तान का व्यवहार है। सुषमाजी ने 2015 में भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिन्दी में भाषण दिया था और उस दैरान भी जम कर पाकिस्तान पर गरजी थीं। तब उन्होंने पाकिस्तान को 'आतंकवाद की फैकट्री' कहकर संबोधित किया था। विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान लगातार यह भी खबर आती रही कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दो साल बाद नवंबर 2018 में सुषमा ने यह एलान कर दिया था कि वे 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगी। दो दिन पहले खुद सुषमा ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने पर ट्वीट किया था और मोदी को बधाई दी।

सुषमा स्वराज की भाषण शैली और वाकपटुता का कोई जोर नहीं था। जब वह बोलती थीं तो विपक्ष भी सत्र रह जाता था। उनके जवाब ऐसे होते थे, कि उसके काट के लिए विरोधी को सोचना पड़ता था। जब वह मनमोहन सरकार में

विपक्ष की नेता थीं, तब उनके लोकसभा में दिये गये भाषण काफी लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के लिए शायरना अंदाज में तंज कसा था और कहा था- 'तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।' वे सरल एवं सादगी पसंद भी थीं। मौलिक सोच एवं राजनीतिक जिजीविषा के कारण उन्होंने पार्टी के लिये संकटमोचन की भूमिका भी निर्भाई। वे राजनीति में उलझी चालों को सुलझाने के लिये कई दफा राजनीतिक जादू दिखाती रही हैं। उनकी जादुई चालों की ही देन है कि वे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रही हैं।

सुषमा स्वराज का निधन एक आदर्श एवं बेबाक सोच की राजनीति का अंत है। वे सिद्धांतों एवं आदर्शों पर जीने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला की प्रतीक थीं। उनके निधन को राजनीतिक जीवन में शुद्धता की, मूल्यों की, राजनीति की, आदर्श के सामने राजसत्ता को छोटा गिनने की या सिद्धांतों पर अड़िगा रहकर न ज्ञानेन, न समझाता करने की समाप्ति समझा जा सकता है। उन्होंने पांच दशक तक सक्रिय राजनीति की, अनेक पदों पर रही, पर वे सदा दूसरों से भिन्न रही। घाल-मेल से दूर। भ्रष्ट राजनीति में बेदाग। विचारों में निडर। टूटते मूल्यों में अडिग। घेरे तोड़कर निकलती भीड़ में मर्यादित। उनके जीवन से जुड़ी विधायक धारणा और

यथार्थपरक सोच ऐसे शक्तिशाली हथियार थे जिसका बार कभी खाली नहीं गया। वे जितनी राजनीतिक थीं, उससे अधिक मानवीय एवं सामाजिक थीं। भारतीय राजनीति की वास्तविकता है कि इसमें आने वाले लोग धुमावदार रास्ते से लोगों के जीवन में आते हैं बरना आसान रास्ता है- दिल तक पहुंचने का। हां, पर उस रास्ते पर नगे पांव चलने वाली एवं लोगों के दिलों पर राज करने वाली राजनेता थे, उनके दिलों-दिमाग में दिली ही नहीं समूचे देश की जनता हार समय बसी रहती थी। काश! सत्ता के मद, करपान के कद, व अहंकार के जह में जकड़े-अकड़े रहने वाले राजनेता उनसे एवं उनके निधन से बोधपाठ ले। निराशा, अकर्मण्यता, असफलता और उदासीनता के अंधकार को उन्होंने अपने आत्मविश्वास, साहसिकता, कर्मठता और जीवन के आशा भरे दीपों से पराजित किया।

सुषमा स्वराज भाजपा की एक नारीरत थी। वे भारतीय संस्कृति की प्रतीक आदर्श महिला थी और यह भारतीय संस्कृति उनमें बसी थी। उनका सम्पूर्ण जीवन अभ्यास की प्रयोगशाला थी। उनके मन में यह बात घर कर गयी थी कि अभ्यास, प्रयोग एवं संवेदना के बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। उन्होंने अभ्यास किया, दृष्टि साफ होती गयी और विवेक जाग गया। उन्होंने हमेशा अच्छे मकसद के लिए काम किया, तारीफ पाने के लिए नहीं। खुद को जाहिर करने के लिए जीवन जीया, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। उनके जीवन की कोशिश रही कि लोग उनके होने को महसूस ना करें। बल्कि उन्होंने काम इस तरह किया कि लोग तब याद करें, जब वे उनके बीच में ना हों। इस तरह उन्होंने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया और जनता के दिलों पर अमिट छोड़ते हुए निरन्तर आगे बढ़ी। वे भारतीय राजनीति का एक अमिट आलेख हैं। सुषमा स्वराज एक ऐसा आदर्श राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिन्हें सेवा और सुधारवाद का अक्षय कोश करता जा सकता है।

सुषमा स्वराज का निधन एक आदर्श एवं बेबाक सोच की राजनीति का अंत है। वे सिद्धांतों एवं आदर्शों पर जीने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला की प्रतीक थीं। उनके निधन को राजनीतिक जीवन में शुद्धता की, मूल्यों की, राजनीति की, आदर्श के सामने राजसत्ता को छोटा गिनने की या सिद्धांतों पर अड़िगा रहकर न ज्ञानेन, न समझाता करने की समाप्ति समझा जा सकता है। उन्होंने पांच दशक तक सक्रिय राजनीति की, अनेक पदों पर रही, पर वे सदा दूसरों से भिन्न रही। घाल-मेल से दूर। भ्रष्ट राजनीति में बेदाग। विचारों में निडर। टूटते मूल्यों में अडिग। घेरे तोड़कर निकलती भीड़ में मर्यादित। उनके जीवन से जुड़ी विधायक धारणा और

उनका आम व्यक्ति से सीधा संपर्क रहा। यही कारण है कि आपके जीवन की दिशाएं विविध एवं बहुआयामी रही हैं। आपके जीवन की धारा एक दिशा में प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि जीवन की विविध दिशाओं का स्पर्श किया। यही कारण है कि कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके जीवन से अछूता रहा हो, संभव नहीं लगता। आपके जीवन की खिड़कियां राष्ट्र एवं समाज को नई दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रही। इन्हीं खुली खिड़कियों से आती ताजी हवा के झोंकों का अहसास भारत की जनता सुदैर्घ काल तक करती रहेगी। सुषमाजी को अलबिदा नहीं कहा जा सकता, उन्हें खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा जा सकता, उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दी जा सकती व्यक्ति ऐसे व्यक्ति मरते नहीं। वे हमें अनेक मोड़ों पर राजनीति में

भारतीय राजनीति का अमिट आलेख है सुषमा स्वराज

[ललित गर्ग]

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति का एक आदर्श चेहरा थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान, कई नए अधिनव दृष्टिकोण, राजनीतिक सोच और कई योजनाओं की शुरुआत की तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया, उनमें जीवन में आशा का संचार किया।

पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री एवं भारतीय राजनीति की संभावनाओं भरी उम्मा सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। मंगलवार की शाम दिल्ली के एस्स में उन्होंने दिल का दौरा पड़ने से अनिम्न सांस ली और अनन्त की यात्रा पर प्रस्थान कर गयी। उनका निधन न केवल भाजपा बल्कि भारतीय राजनीति के लिए दुखद एवं गहरा आघात है। उनका असमय देह से विदेह हो जाना सभी के लिए संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता, अनित्यता, अशावता का बोधपाठ है। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। उनका निधन एक युग की समाप्ति है। भाजपा के लिये एक बड़ा आघात है, अपूरणीय क्षति है। आज भाजपा जिस मुकाम पर है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाने में जिन लोगों का योगदान है, उनमें सुषमाजी अग्रणी हैं। वे भारतीय राजनीति की सतरंगी रेखाओं की सादी तस्वीर थी। उन्हें हम भारतीयता एवं भारतीय राजनीति का ज्ञानकोष कह सकते हैं, वे चित्रता में मित्रता की प्रतीक थी तो गहन मानवीय चेतना की चित्रेरी जुझारू, नीड़, साहसिक एवं प्रखर व्यक्तित्व थी।

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति का एक आदर्श चेहरा थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान, कई नए अधिनव दृष्टिकोण, राजनीतिक सोच और कई योजनाओं की शुरुआत की तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया, उनमें जीवन में आशा का संचार किया। पिछली बार वे नरेन्द्र मोदी सरकार में एक सशक्त एवं कद्दावर मंत्री थी। भाजपा में वे मूल्यों की राजनीति करने वाली नेता, कुशल प्रशासक, योजनाकार थी। दिल्ली की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान

था। यह महज संयोग ही है कि एक महीने से भी आदर्श चेहरा थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान, कई नए अधिनव दृष्टिकोण, राजनीतिक सोच और कई योजनाओं की शुरुआत की तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया, उनमें जीवन में आशा का संचार किया।

पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री एवं भारतीय राजनीति की संभावनाओं भरी उम्मा सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। मंगलवार की शाम दिल्ली के एस्स में उन्होंने दिल का दौरा पड़ने से अनिम्न सांस ली और अनन्त की यात्रा पर प्रस्थान कर गयी। उनका निधन न केवल भाजपा बल्कि भारतीय राजनीति के लिए दुखद एवं गहरा आघात है। उनका असमय देह से विदेह हो जाना सभी के लिए संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता, अनित्यता, अशावता का बोधपाठ है। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। उनका निधन एक युग की समाप्ति है। भाजपा के लिये एक बड़ा आघात है, अपूरणीय क्षति है। आज भाजपा जिस मुकाम पर है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाने में जिन लोगों का योगदान है, उनमें सुषमाजी अग्रणी हैं। वे भारतीय राजनीति की सतरंगी रेखाओं की सादी तस्वीर थी। उन्हें हम भारतीयता एवं भारतीय राजनीति का ज्ञानकोष कह सकते हैं, वे चित्रता में मित्रता की प्रतीक थी तो गहन मानवीय चेतना की चित्रेरी जुझारू, नीड़, साहसिक एवं प्रखर व्यक्तित्व थी।

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति का एक आदर्श चेहरा थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान, कई नए अधिनव दृष्टिकोण, राजनीतिक सोच और कई योजनाओं की शुरुआत की तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया, उनमें जीवन में आशा का संचार किया। पिछली बार वे नरेन्द्र मोदी सरकार में एक सशक्त एवं कद्दावर मंत्री थी। भाजपा में वे मूल्यों की राजनीति करने वाली नेता, कुशल प्रशासक, योजनाकार थी। दिल्ली की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान

था। यह महज संयोग ही है कि एक महीने से भी आदर्श चेहरा थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान, कई नए अधिनव दृष्टिकोण, राजनीतिक सोच और कई योजनाओं की शुरुआत की तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया, उनमें जीवन में आशा का संचार किया।

2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में दिल्ली ने अपने दो पूर्व महिला मुख्यमंत्रियों को खो दिया है। 20 जुलाई को दिल्ली की सबसे लंबे अंतराल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का निधन हुआ तो महज दो हफ्ते बाद दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भी चल बसीं। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैटंप में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। अम्बाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में ज्ञात की पढ़ाई करने के बाद सुषमाजी ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की डिप्री ली। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में सुषमाजी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। जुलाई 1975 में उनका विवाह सुप्रीम कोर्ट के ही सहकर्मी स्वराज कौशल से हुआ। आपातकाल के दौरान सुषमाजी ने जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपातकाल के बाद वह जनता पार्टी की सदस्य बन गयी। इसके बाद 1977 में पहली बार सुषमाजी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज 25 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल सरकार में राज्य की श्रम मंत्री बन कर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। दो साल बाद ही उन्हें राज्य जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमाजी भाजपा में शामिल हो गयीं। वह अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गयीं और बीजेपी-लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गयीं। वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि दिसंबर 1998 में उन्होंने राज्य विधानसभा सीट से इसीफा देते हुए राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बेळ्ळरी से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव में उत्तरी लेकिन वे हार गयीं। फिर साल

29 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र में दिया सुषमाजी का भाषण खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर चलाने की वकालत की। इस भाषण में उन्होंने



धारा 370-मोदी सरकार का अत्यंत प्रशंसनीय कदम

[ब्रजकिशोर सिंह]

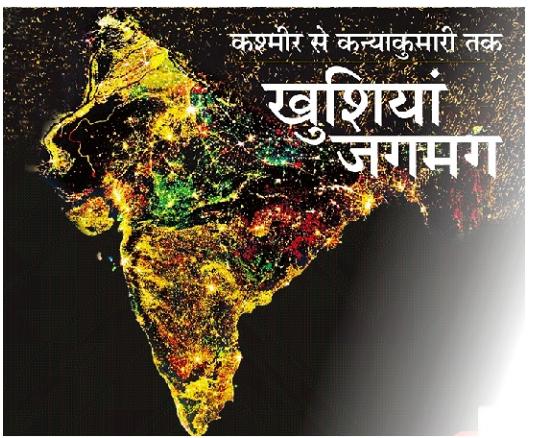
मित्रों, आज और अबसे कुछ ही देर पहले भारत की संघ सरकार ने एक अत्यंत प्रशंसनीय प्रस्ताव संसद में रखा है। जिसके अनुसार अब बहुत जल्द भारतीय संविधान से धारा 370 के एक उपखंड को छोड़कर बांकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही उसने संविधान की धारा 35 ए को समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव भी संसद के समक्ष रखा गया है। अबसे जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश होगा यद्यपि वहाँ विधानसभा बनी रहेगी। जबकि लद्दाख अब बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा। सबसे अच्छी बात प्रस्ताव में यह है कि अबसे संसद द्वारा 1952 से लेकर आज तक पारित किए गए सारे कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। मित्रों, मोदी सरकार के इस कदम की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी क्योंकि इस धारा के कारण जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जिसके चलते भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुँच रही थी। आज अमर शहीद डॉ. श्याम प्रसाद मुख्यर्जी की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिल गई होगी जिन्होंने एक राष्ट्र दो उद्योगों की स्थापना नहीं करती था। अबसे में यह एक उद्योगपति वहाँ उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकता था। ऐसे में कोई उद्योगपति वहाँ उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकता था। अब यह प्रतिबन्ध समाप्त हो गया है ऐसे में निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर का तेज़ औद्योगिक व आर्थिक विकास होगा। मित्रों, धारा 370 पर जम्मू-कश्मीर के उन दो परिवारों का विरोध तो फिर भी समझ में आता है जिन्होंने इसे अपनी निजी जागीर बना लिया

था लेकिन कांग्रेस द्वारा विरोध कर्हीं से भी समझ में नहीं आता है। क्या कांग्रेस आज जिस स्थिति में है आगे उससे भी ख़राब स्थिति में जाना चाहती है?

मित्रों, कुल मिलाकर जबसे केंद्र में मोदी सरकार आई है तबसे ही उसने जम्मू-कश्मीर में बहुमुखी कदम उठाए हैं। एक तरफ तो वो वहाँ के शांतिप्रिय लोगों का समर्थन कर रही है वहाँ दूसरी तरफ आंतंकवादियों के खिलाफ करारा प्रहर भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने पंडित नेहरू द्वारा की गई कई ऐतिहासिक भूलों में से एक को दूर कर दिया है। इतना ही नहीं जिस तरह से 9 अगस्त को हम अगस्त क्रांति दिवस कहते हैं उसी प्रकार आज 5 अगस्त के दिन को भारतीय इतिहास में भारतीय संविधान भूल सुधार दिवस के रूप में याद किया जाएगा।

इस समय पूरे भारत से जश्न मनाए जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं और मैं भी मिठाई, पटाखे और रंग लाने जा रहा हूँ क्योंकि आज एक साथ होली और दिवाली मनाने का दिन है और इसके लिए केंद्र सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है।

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं



संविधान को मिला नया विस्तार

[हरबंश दीक्षित]

विधि विशेषज्ञ

जम्मू-कश्मीर से जुड़ी अधिसूचना को लेकर पूरे देश में काफी बहस छिड़ी हुई है। उसे लेकर परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग केंद्र सरकार की नीयत को लेकर आशंका जata रहे हैं, तो कुछ लोगों को सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर असमंजस है। मीडिया में आने वाली कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो कुछ लोग यह मान बैठे हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य तुरंत प्रभाव से दो भागों में बांट दिया गया है। वास्तविक स्थिति इससे अलग है। पहला यह कि अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया गया है। इसे इस तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इस अधिसूचना का दूसरा प्रभाव यह है कि इसके द्वारा भारत के संविधान को समग्र रूप से जम्मू-कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 2 से 5 में दिए गए अधिकारों के तहत केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव एक विधेयक के रूप में संसद के सामने रखा गया है। इसके द्वारा संविधान के कई उपबंधों में संशोधन होगा, और यह तभी लागू होगा, जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए।

गृह मंत्री के राज्य सभा के बयान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में राष्ट्रपति की अधिसूचना के बारे में सदन को सूचित किया गया। दूसरे भाग में जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के लिए जम्मू-

कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को सदन के सामने रखा गया। इसके द्वारा जम्मू-कश्मीर को ऐसा केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी विधानसभा होगी और लद्दाख को ऐसा केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी विधानसभा नहीं होगी।

राष्ट्रपति की अधिसूचना में कहा गया है कि यह पूर्व की इस तरह की सभी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करेगी और तुरंत प्रभाव से लागू होगा, जिसका मतलब यह हुआ कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह इस व्यवस्था को लागू करे। विभिन्न वर्गों के बीच की आर्थिक खाई को कम करे। महिलाओं के लिए विशेष प्रसूति सुविधाएं मुहैया कराए। गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता दे। गरीब छात्रों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था करे। महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन सुनिश्चित करे और नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करे। मूलभूत कर्तव्यों के लागू होने का असर यह होगा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षित करने तथा बच्चों को स्कूल भेजने जैसे दायित्व भी वहाँ के नागरिकों पर उसी तरह से प्रभावी हो सकेंगे।

वहाँ के नागरिक को समानता का मूल अधिकार हासिल होगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक हासिल होगा। जाति-धर्म-मूल-वंश या लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं होगा। समाज के वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ लेकर मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। छुआछूत के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव समाप्त हो सकेंगे। अनुच्छेद 35-ए एक प्रशासनिक आदेश था, सभी को वहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का मूल किया गया था। इसे संसद के सामने नहीं रखा गया और इस तरह से पेश किया गया, जैसे कि यह संविधान का हिस्सा हो। इसका सबसे अधिक आश्रयजनक पक्ष तो यह है कि इसे जिस अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जारी किया

गया, उसकी शुरुआत ही संविधान को नकारने से होती है। कहा गया था कि अनुच्छेद 35-ए में उल्लिखित विषयों पर बनाए गए कानून का भारत के संविधान के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। इसका सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि जिस संविधान में एक विराम या अल्पविराम में भी संशोधन के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है, उसमें केवल प्रशासनिक आदेश द्वारा आमूल परिवर्तन कर दिया गया, और वह रहस्यमय ढंग से पिछले 65 वर्षों से लागू रहा। लोगों को मूल अधिकारों से वंचित करता रहा। यहाँ तक कि संविधान के मूल ढांचे को लेकर कोई सार्थक बहस नहीं की गई।

मीडिया की खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की मौजूदा अधिसूचना तथा राज्य पुनर्गठन के संबंध में मूल बहस सरकार के क्षेत्राधिकार को लेकर है। इस संबंध में कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली यह कि अनुच्छेद 35-ए की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी। उसे संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के तहत जारी किया गया था। अनुच्छेद 370 (1) में व्यवस्था है कि उसे राज्य सरकार की सहमति के बगैर जारी नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 35-ए को जोड़ने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की सहमति से 14 मई, 1954 को जारी किया गया था।

अधिसूचना को स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद-370 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से जारी किया गया है। इसलिए इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है। जिस प्रक्रिया द्वारा पिछली अधिसूचना से अनुच्छेद 35-ए को लागू किया गया था, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए पिछली अधिसूचना को निष्प्रभावी कर जम्मू-कश्मीर में संविधान को समग्रता से लागू कर दिया गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कांग्रेस अपने महाविनाश की ओर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है ?

[राजीव गुप्ता]

370 और 35ए जैसी संविधान की अस्थायी धाराओं को मोदी सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया है। जो काम पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर सकी और जिसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, आखिर उस काम को मोदी सरकार ने बिना किसी अड़चन के अंजाम देकर एक ऐतिहासिक काम किया है। इस काम को अंजाम देने की योजना 2015 से चल रही थी और इसे लागू करने में जिस तरह की गोपनीयता रखी गयी, वह काबिले तारीफ़ है।

पूरा देश इन असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण धाराओं के हटाए जाने से बेहद खुश है और जश्न में डूबा हुआ है लेकिन कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी पार्टियों को देश-हित में लिया गया मोदी सरकार का यह फैसला भी रास नहीं आ रहा है और वे सब उसका जोर-शोर से विरोध कर रही हैं। जिन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के सन्दर्भ में लिए गए इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले का विरोध किया है, उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डी एम के, एम डी एम के, सी पी एम, आर जे डी, जनता दल-यूनाइटेड, पी डी पी और नेशनल कांफ्रेंस शामिल हैं कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जा सकता था, लेकिन देश हित में लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के खुलकर विरोध में आने के बाद कांग्रेस अपने बजूद को कब तक बचा पाएगी, यह कहना मुश्किल है। नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के पास यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था, जब वह इसका समर्थन करके अपने ऊपर देशद्रोही पार्टी लगे होने का टप्पा हमेशा के लिए मिटा सकती थी लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से चूक गयी है। इस बार कांग्रेस ने वह देशद्रोही कहा जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के उन सभी समर्थकों को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया होगा कि देश की अधिकांश जनता कांग्रेस को देशद्रोही क्यों मानती है। मजे की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में कांग्रेसी गुलाम नबी आज़ाद से यह विनती कर रहे थे कि अगर उन्हें इन धाराओं को हटाने में कुछ गलत लग रहा है, तो कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल उस पर वेजह हंगामा करने की बाजाए उस पर स्वस्थ चर्चा करें लेकिन अमित शाह की इस बात को दरकिनार करते हुए विपक्षी सांसद संसद के अंदर ही संविधान की प्रतियों को फाड़ने लगे और खुल्मखुल्मा देशद्रोह पर उत्तर आए। संसद की कार्यवाही का आजकल सीधा प्रसारण होता है और उसे पूरे देश की जनता देख रही होती है। सोशल मीडिया भी पिछले कई सालों में काफी ताकतवर साधन बन चुका है और देश की जनता क्या सही है और क्या गलत है, सब समझती है। मेरे अपने विचार में इन दोनों धाराओं से सिर्फ़ तीन लोगों को फायदा था। जिन तीन लोगों को इन दोनों धाराओं से फायदा मिल रहा था, उनमें दो तो अपने ही देश में हैं- यानि अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस और महबूबा की पीड़ीपी तीसरा व्यक्ति जिसे इन दोनों धाराओं का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था, वह है दुश्मन देश पकिस्तान क्योंकि जम्मू-कश्मीर को मिले इस विशेष दर्जे की वजह से ही वह उसे कश्मीर समस्या का नाम देने में सफल हो रहा था। इन दोनों धाराओं के विरोध करने में कांग्रेस का अपना कोई हित नहीं था लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है, इसका जबाब कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खोजना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने असितत्व के संकट से जूझ रही है, उसके पास अपने असितत्व को बचाने के मौके वैसे भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। काफी समय बाद एक सुनहरा मौका कांग्रेस के पास खुद चलकर आया था, जब कांग्रेस अपने बजूद को बचाकर खुद को दुबारा से खड़ा करने की दिशा में चल सकती थी लेकिन जो कहावत है कि-विनाश काले विपरीत बुद्धि उसे चरितार्थ करते हुए कांग्रेस ने अपने महाविनाश की कहानी का अंतिम अध्याय खुद ब खुद लिख दिया है।

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं